दैनिक
सांध्य प्रकाश
भोपाल की धड़कन

वर्ष 54/ अंक 14/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10

संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल

■आर.एन.आई 22296/71 ■डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

भोपाल, बुधवार 31 जुलाई 2024 भोपाल से प्रकाशित

dainiksandhyaprakash.in

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका: नहीं करने पर देना होगा 5 हजार तक का जुर्माना

सांध्यप्रकाश विशेष

दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील होने के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने जारी की प्रेस रिलीज

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और लेखक हैं, जो देश के सम्मानित शिक्षकों में से एक हैं।डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की थी। साथ ही, पारिवारिक उम्मीदों से प्रभावित होकर, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू

की और साल 1996 में ढ्ढक्र384 हासिल की थी। गृह मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद, उन्होंने शिक्षण के अपने जुनून का पालन करने का फैसला किया और 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की।

दिल्ली के राजिंदर नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद एमसीडी ने करीब 20 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है, जिसमें विकास दिव्यकीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है. विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर ने सील किए जाने के बाद आज 30 जुलाई 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी की है. इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कई बातें सामने रखी हैं

हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की. वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें. इस देरी के लिये हम हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं.

शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई, पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें.

इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है, वह पूरी तरह न्यायसंगत है. बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिये निश्चित दिशानिर्देश लागू करे. इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं.

कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं. इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हैं. डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है. इसी तरह, 'दिल्ली मास्टरप्लान-2021', 'नैशनल बिल्डिंग कोड', 'दिल्ली फायर रूल्स' और 'यूनिफाइड बिल्डिंग बाई-लॉज़' के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है. 'दिल्ली मास्टरप्लान-2021' को छोड़कर किसी भी दस्तावेज़ में कोचिंग संस्थानों के लिये स्पष्ट प्रावधान नहीं दिये गए हैं।

'सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति' गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। हाल के हफ्तों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए अब तक उठाए गए कदमों को लेकर सवाल पूछा गया था. गृह मंत्रालय ने सदन में लिखित जवाब में इस सवाल का जवाब दिया.

जम्मू-कश्मीर में एक महीने से अधिक समय से आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच, केंद्र सरकार ने आज लोकसभा को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सांसद प्रदीप कुमार सिंह के 'स्टारलेस प्रश्न' के लिखित उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया है। प्रदीप कुमार सिंह ने 'स्टारलेस क्वेश्चन' में पूछा था कि क्या सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को

आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है।

प्रश्न का उत्तर देते हुए, सरकार ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ निरंतर उपायों में राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर अनुशासन पर जोर दिया गया है। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार का दृष्टिकोण आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है।

सरकार के जवाब के अनुसार, जिसमें 21 जुलाई, 2024 तक का डेटा सूचीबद्ध है, इस वर्ष इस क्षेत्र में 11 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन दर्ज किए गए। अब तक सुरक्षा बलों के 14 जवान मारे जा चुके हैं और 14 नागरिकों की जान जा चुकी है.

वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 175 मौतें, 220 लापता

1 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3 हजार से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया

वायनाड। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 175 हो गई हैं। 131 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 220 के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में हुई थीं। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं।

आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वॉड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देर रात तक 1 हजार लोगों का रेस्क्यू किया गया, 3 हजार लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज परेशानी हो सकती है।

सेना ने दो रिसॉर्ट से 19 टूरिस्ट को बचाया

सेना ने मुंडक्कई गांव के बाहर स्थित इला रिसॉर्ट और वाना रानी रिसॉर्ट में फंसे 19 टूरिस्ट को बुधवार को निकाला। ये घटना के बाद से यहीं फंसे हुए थे। डिफेंस प्रवक्ता के मुताबिक, 122 इन्फैंट्री बटालियन मद्रास के जवानों ने रस्सियों के सहारे सभी नागरिकों को चूरलमाला तक सुरक्षित निकालने के लिए एक मानव पुल बनाया।

स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टलीं

हादसे के बाद राज्य में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 12 जिलों में 30 जुलाई को स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई। केरल यूनिवर्सिटी ने 30 और 31 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा।

वायनाड जा रहीं हेल्थ मिनिस्टर एक्सीडेंट में घायल

लैंडस्लाइड की घटना का जायजा लेने वायनाड जा रहीं केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज बुधवार (31 जुलाई) को सुबह करीब साढ़े 7 बजे एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं। उन्हें मलप्पुरम स्थित मंजेरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना एक स्कूटर सवार को बचाने के चलते हुई।

राहुल और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरा रद्द किया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से वायनाड दौरा रद्द कर दिया है। राहुल ने आज कांग्रेस सांसदों के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में वायनाड में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दो मिनट का मौन रखा।

केंद्रीय मंत्री पहुंचे वायनाड

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। जॉर्ज कुरियन ने कहा, प्रधानमंत्री भूस्खलन की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्होंने मुझे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24×7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। राज्य को हरसंभव सहायता पहुंचाने के लिए भी काम किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी ओर बचाव कर्मियों की आवाजाही स्थापित करने में सहायता के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस जमोरिन को भी तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्र की तरफ से भी अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएंगे।

डेयरी प्रोडक्ट फैक्ट्री संचालक के घर-फैक्ट्री पर ईओडब्ल्यू का छापा

फर्जी तरीके से फूड प्रोडक्ट विदेश भेजने का आरोप, सीहोर-भोपाल समेत 12 ठिकानों पर कार्रवाई

भोपाल। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने मामले में बुधवार को जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (पनीर फैक्ट्री) के मालिकों के ठिकानों पर छापा मारा है। 25 से ज्यादा अधिकारी भोपाल और सीहोर में 12 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। टीम सुबह करीब 11 बजे पहुंची। इनमें शाहपुरा और 10

नंबर स्टॉप स्थित घर, दफ्तर और सीहोर स्थित फैक्ट्री भी शामिल है। यहां से अहम दस्तावेज और फाइलें जब्त की गई हैं। कंपनी के मालिकों से पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के डायरेक्टर किशन मोदी हैं। इनके साथ फैक्टी के अन्य अधिकारी पारुल मोदी और राजेंद्र मोदी पर 24 जुलाई को ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर विदेश में सप्लाई किए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार करने का आरोप है। ये छापेमारी एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर चल रही है।

प्रशासन ने की थी फैक्ट्री सील

दरअसल, सीहोर के पिपलिया मीरा स्थित जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (पनीर फैक्ट्री) को प्रशासन ने 16 जुलाई को बंद करा दिया था। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर की थी। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर बिजली कंपनी ने बिजली कनेक्शन काट दिया था, जिससे उत्पादन बंद हो गया था। अब फैक्ट्री जब तक चालू नहीं होगी, तब तक कि उद्योग जल प्रदूषण नियंत्रण की पूर्ण व्यवस्था नहीं करता है। जयश्री गायत्री फूड्स कंपनी पर जिला प्रशासन द्वारा यह दूसरी बार सख्त कार्रवाई की गई है। इससे पहले, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने को लेकर नारेबाजी

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का बुधवार (31 जुलाई) को आठवां दिन है। आज विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग की और इसे लेकर खासा हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही स्थगित हो कर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई।

लोकसभा में विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। प्रश्नकाल में वे नरेंद्र मोदी सदन में आओ के नारे लगा रहे थे। इस सबके बीच प्रश्नकाल जारी रहा। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा- प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। इस पर स्पीकर ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। कांग्रेस के चीफ व्हिप मनिकम टैगोर ने जाति जनगणना और महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। पार्टी के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने असम में बाढ़ और केरल से सांसद हिबी ईडन ने वायनाड लैंडस्लाइड पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की है।

कोचिंग हादसा- दिल्ली हाईकोर्ट बोला- सिस्टम की मिलीभगत इसकी जिम्मेदार

नई दिल्ली। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग में तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा- इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्योर हैं। ये सब मिलीभगत से हुआ है। सभी ब्लेम-गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी।

एमएसीडी अधिकारियों से पूछो नाली कहां, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते है। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा- अगर जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की, तो यह केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं।

गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की

नई दिल्ली। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है।

अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। 28 जुलाई को लिखे अपने पत्र में गडकरी ने कहा -

Smt. Nirmala Sitharaman Ji,

Hope this finds you in the best of health and spirit.

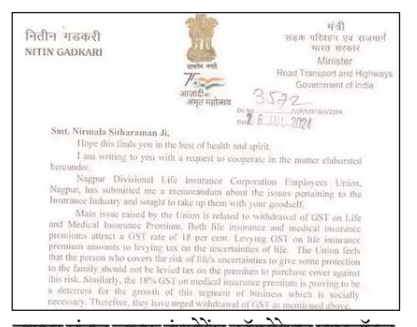

I am writing to you with a request to cooperate in the matter elaborated hereunder.

Nagpur Divisional Life Insurance Corporation Employees Union, Nagpur, has submitted me a memorandum about the issues pertaining to the Insurance Industry and sought to take up them with your goodself.

Main issue raised by the Union is related to withdrawal of GST on Life and Medical Insurance Premium. Both life insurance and medical insurance premiums attract a GST rate of 18 per cent. Levying GST on life insurance premium amounts to levying tax on the uncertainties of life. The Union feels that the person who covers the risk of life's uncertainties to give some protection to the family should not be levied tax on the premium to purchase cover against this risk. Similarly, the 18% GST on medical insurance premium is proving to be a deterrent for the growth of this segment of business which is socially necessary. Therefore, they have urged withdrawal of GST as mentioned above.

नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एम्पलॉइज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध किया है। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने के लिए संबंधित है, दोनों में ही 18 प्रतिशत की जीएसटी लगता है।

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करने के लिए इंश्योरेंस खरीदता है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा - आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।

झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत

- 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार (31 जुलाई) को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच, झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। इधर, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी 50 प्रतिशत बारिश हो गई है। प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बुधवार से फिर से प्रदेश में झमाझम का दौर शुरू हो सकता है।

राजस्थान और बिहार में मानसून धीमा पड़ा है। राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर में टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया। बिहार में भी ट्रफ लाइन राज्य की सीमा से बाहर है,

जिसके चलते बारिश नहीं हो रही है। कई जिलों में गर्मी और उमस है। गोपालगंज में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के पास भारी बारिश के चलते घाट-सड़कें बह गए। उत्तरकाशी में 30 जुलाई को सामान्य से 2 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार1 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में अतिभारी बारिश (20 सेमी से ज्यादा) का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक में भारी बारिश (12 सेमी से ज्यादा) की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, गुजरात में 7 सेमी के आसपास बारिश हो सकती है।

प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चैयरमैन बनाया गया

नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) को प्रीति सूदन के रूप में नया चैयरमैन मिल गया। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। चैयरमैन नियुक्त होने से पहले, सूदन 29 नवंबर, 2022 से यूपीएससी में मेंबर के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुईं सूदन को सरकारी प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 37 सालों का अनुभव है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, प्रीति सूदन ने कोविड-

19 महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूदन ने इससे पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है और महिला एवं बाल विकास तथा रक्षा मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके राज्य-स्तरीय अनुभव में वित्त एवं योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि में भूमिकाएँ शामिल हैं।

प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। सूदन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमफिल और सामाजिक नीति एवं नियोजन में एमएससी की डिग्री ली है। इसके अलावा, सूदन ने वर्ल्ड बैंक के साथ सलाहकार के रूप में काम किया है और तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन की अध्यक्ष और मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी की उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है। वह ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप की अध्यक्ष और महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल की सदस्य भी रहीं।

झारखंड सरकार के पारसनाथ पर्वत पर किए गए कदमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई

अहमदाबाद। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की अध्यक्षता में एक डिवीजन बेंच पारसनाथ पर्वत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 31 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी। यह पर्वत झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जो जैन समुदाय के लिए सबसे पूजनीय तीर्थस्थल है। सिविल अपील संख्या 5596-5600/2009 में दाखिल की गई डू संख्या 156891/2024, दर्शनाबेन नयनभाई शाह द्वारा दायर की गई है, जो इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने वाली गतिविधियों को तत्काल रोकने के लिए कोर्ट के आदेशों की मांग करती है।पारसनाथ पर्वत, जिसे शिखरजी के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल माना जाता है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक जैन साधुओं ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है। सदियों से, केवल जैन समुदाय ही नहीं बल्कि विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों द्वारा भी इस पर्वत को उसकी धार्मिक महत्वता के लिए मान्यता मिली है। जैसे अयोध्या हिंदुओं के लिए, बोधगया बौद्धों के लिए, स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए, मक्का मुसलमानों के लिए और वेटिकन कैथोलिकों के लिए पवित्र है, वैसे ही यह पर्वत जैनों के लिए पवित्र है। इस याचिका में, दर्शनाबेन शाह, जैन समुदाय के एक निष्ठावान सदस्य, हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा की गई कई गतिविधियों को उजागर करती हैं, जो पर्वत की पवित्रता को खतरे में डालती हैं। याचिका में निम्नलिखित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है-झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने से बढ़ी हुई पर्यटकों की आवन-जावन के कारण पर्वत पर नए साल की पिकनिक और खाने-पीने की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, जिसे जैनों द्वारा अपवित्र माना जाता है। झारखंड राज्य ने राज्य में 5 प्रमुख स्थानों पर पर्यटन विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है, जिनमें से एक यह शिखरजी पर्वत है। इको-टूरिज्म भी झारखंड सरकार की योजनाओं का हिस्सा है। जैन परंपरागत रूप से नंगे पांव तीर्थयात्रा को श्रद्धा का चिन्ह मानते हैं, इसलिए पर्वत पर रोपवे बनाने के प्रस्ताव का जैन समुदाय द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। पहले की रोपवे योजनाओं को ऐसे ही विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था।

सभी पेमेंट एवं फिनटेक ऑफरिंग्स को साथ लाया फ्लिपकार्ट पे

मुंबई, एजेंसी। त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी सहूलियत देते हुए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने फाइनेंशियल एवं पेमेंट ऑफरिंग्स से जुड़ी अपनी सभी सेवाओं को अपने एप पर फ्लिपकार्ट पे के अंतर्गत एक साथ लाने की घोषणा की है। नए फिनटेक प्लेटफॉर्म को ग्राहकों का जुड़ाव बेहतर करने और उन्हें पेमेंट का सुगम अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। फ्लिपकार्ट पे - पे, सेव एंड अर्न की टैगलाइन के साथ फ्लिपकार्ट पे से ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा और यह ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बनकर सामने आएगा, जिससे वे सहूलियत के साथ फ्लिपकार्ट की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। 2013 में गिफ्ट कार्ड की लॉन्चिंग के साथ फिनटेक सर्विस में कदम रखने के बाद से फ्लिपकार्ट लगातार अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को विस्तार दे रहा है जिससे भुगतान के आसान विकल्पों तक पहुंच को सहज बनाया जा सके। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग के साथ इस सफर को आगे बढ़ाया गया, जिसे आज 40 लाख से ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं। अपने आकर्षक रिवार्ड्स एवं सेविंग्स बेनिफिट के कारण यह को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लोगों के पसंदीदा क्रेडिट कार्ड्स में शामिल हो गया है। शॉपिंग के संपूर्ण अनुभव को बेहतर करने की प्रतिबद्धता के साथ फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट पे लेटर की शुरुआत की, जिससे ग्राहकों को ईएमआई के माध्यम से भुगतान करने का आसान विकल्प मिलता है।

जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने प्रमुख निवेशकों एलआईसी एमएफ फंड्स, मोर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज को इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी

चंडीगढ़, एजेंसी। स्टील ट्यूब बनाने वाली तेजी से बढ़ती कंपनी, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीएसईः 534600, एनएसई-जेटीएलआईएनडी) ने आज घोषणा की है कि कंपनी के बोर्ड ने एलआईसी एमएफ फंड्स, मोर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज और अन्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस निवेश से कंपनी को कुल 299.99 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। कंपनी ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए बेहतरीन परिणाम घोषित किए है। इस दौरान कंपनी की आय बढ़कर 5153.8 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 5048 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि बाजार में विस्तार, उत्पादों की बढ़ती मांग, बिक्री में वृद्धि और नए उत्पादों के कारण हुई है। कंपनी का एबिटा भी बढ़कर 438.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि है। यह बेहतर लागत नियंत्रण और संचालन क्षमता के कारण संभव हुआ है। कंपनी एबिटा मार्जिन भी बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले साल 7.2 प्रतिशत था।कंपनी ने इस तिमाही में 85,674 टन स्टील ट्यूब बेचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि है। इनमें से 25 प्रतिशत यानी 21,261 टन विशेष प्रकार के उत्पाद थे। इसके अलावा, कंपनी ने इस तिमाही में 5,917 टन उत्पादों का निर्यात किया

कैप्टन पाइप्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली तिमाही के लिए शानदार आय की घोषणा की

मुंबई, एजेंसी। कैप्टन पाइप्स लिमिटेड (बीएसईः 538817), पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में से एक, ने 26 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटिड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली तिमाही के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए, मैनेजमेंट ने कहा कि, हमें वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए कैप्टन पाइप्स लिमिटेड के मजबूत प्रदर्शन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू साल-दर-साल 8.7 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष की समान अवधि में 1911.88 लाख रुपये की तुलना में 2077.39 लाख रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि हमारे स्ट्रेटिजिक इनीशिएटिव्स और हमारे स्टेकहोल्डर्स को वैल्यू देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारे एबिटा में साल-दर-साल 44 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो फाइनेंशियल ईयर 24 की पहली तिमाही में 180.86 लाख रुपये से फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली तिमाही में 260.52 लाख रुपये बढ़ गई है। यह मज़बूत प्रदर्शन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट पर हमारे केंद्रित प्रयासों से प्रेरित था। हमारे प्रोडक्ट मिक्स को ऑप्टीमाइज्ड करने और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के साथ, हमारा एबिटा मार्जिन 221 आधार अंक बढ़कर 12.54 प्रतिशत हो गया।

दक्षिण एशिया में एसएसीई-स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए

790,000 ईयू-फंडेड मिशन में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी शामिल

नई दिल्ली , एजेंसी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, ईयू-फंडेड 'नॉलेज डेवलपमेंट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांज़िशन' प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे दक्षिण एशिया में एडवांस सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रणी प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। प्रोजेक्ट 'नॉलेज डेवलपमेंट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांज़िशन' के तहत दरअसल छह भागीदार संस्थानों के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। ये संस्थान हैं- यूनिवर्सिटी ऑफ़ जैवस्काइला (फिनलैंड), एफएच जोआनम गेसेलशाफ्ट एमबीएच (ऑस्ट्रिया), बिमटेक (भारत), निरमा यूनिवर्सिटी (भारत), प्रिंस ऑफ़ सोंगक्ला यूनिवर्सिटी (थाईलैंड), और पेयप यूनिवर्सिटी (थाईलैंड)। यूनिवर्सिटी ऑफ़ जैवस्काइला के डॉ. भावेश सरना इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भारत से नेशनल लीड के रूप में बिमटेक की डॉ. वीनू शर्मा इसका नेतृत्व कर रही हैं। बिमटेक के संकाय सदस्यों में डॉ. के. के. उपाध्याय, डॉ. प्रतीक जैन, डॉ. अनुपमा सिंह और सुश्री स्वधा

राय शामिल हैं।

जनवरी 2024 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सस्टेनेबल एंड सर्कुलर इकोनॉमी (एसएसीई) में विश्वविद्यालय के संकाय, छात्रों और शुरुआती चरण के पेशेवरों की शिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए चार ष्ठ केंद्र स्थापित करना है। ये केंद्र शिक्षण और अनुसंधान के लिए डिजिटल हब के रूप में कार्य करेंगे, जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने और विविध शिक्षण सामग्री के साथ व्यापक एसएसीई कोर्स विकसित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।

यूरोपीय एजुकेशन एंड कल्चर एक्जीक्यूटिव एजेंसी (ईएसीईए) के नेतृत्व में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के मुख्य पाठ्यक्रम में एसएसीई सिद्धांतों को एकीकृत करना है। 22 जनवरी, 2024 को थाईलैंड के पेयप विश्वविद्यालय में इस प्रोजेक्ट से संबंधित उद्घाटन बैठक में फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत और थाईलैंड के साझेदार विश्वविद्यालयों के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

पीडब्ल्यूसी इंडिया भारत के विकास की कहानी के लिए प्रतिबद्ध

भोपाल। पीडब्ल्यूसी इंडिया फाउन्डेशन पिछले तीन सालों से, कोरबेट फाउन्डेशन, वन विभाग, राज्य सरकार तथा ग्रामीण समुदायों की साझेदारी में कान्हा टाइगर रिज़र्व के आस-पास के गांवों में पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। भारत के विकास की कहानी में योगदान देने वाले ये प्रयास विभिन्न हितधारकों के सहयोग से ग्रामीण समुदायों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये प्रयास केन्द्रीय बजट 2024 के अनुरूप भी हैं, जिसमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक रूप से ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ईंधन के लिए जंगलों से मिलने वाली लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए स्वच्छ एवं प्रभावी कुकस्टोव वितरित किए गए, जिससे न सिर्फ कार्बन फुटप्रिन्ट में कमी आई, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। इसी तरह हरित कवर बढ़ाने के लिए 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 11,000 पौधे लगाए गए। इसके अलावा पौधों की आक्रामक प्रजातियों को हटाने से स्थानीय प्रजातियों को पनपने और जैव-विविधता के संरक्षण में मदद मिली। समुदाय एवं वन्यजीवन को जल का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 350,000-450,000 लीटर क्षमता का एक तालाब भी बनाया गया।इसके बाद लोगों को आजीवका के स्थायी अवसर- खासतौर पर हरित आजीकिता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना को विस्तारित किया गया। इससे ग्रामीणों को नर्सरी प्रबन्धन, शहद उत्पादन, लकड़ी के अलावा वनों से मिलने वाले अन्य उत्पादों के संग्रहण जैसे काम करने का अवसर मिला। इस तरह पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन मिले। इस अवसर पर पीडब्ल्यूसी इंडिया फाउन्डेशन के वाईस चेयरमैन जयवीर सिंह ने कहा, ''पीडब्ल्यूसी इंडिया फाउन्डेशन और कोरबेट फाउन्डेशन के बीच साझेदारी इस बात का प्रमाण है कि निजी एवं सामाजिक क्षेत्र एक साथ मिलकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बुनियादी जानकारी रखने वाले सामाजिक संगठन, निजी कंपनियों के संसाधानों जैसे समय, कौशल, फंड्स आदि का उपयोग कर समुदायों के विकास के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की क्षमता रखते हैं। इसी संदर्भ में हमारे प्रयासों को जारी रखते हुए, कोरबेट फाउन्डेशन ने नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण एवं स्थायित्व के मूल्यों पर प्रेरित करने के लिए बच्चों की एक पुस्तक 'टेल्स ऑफ कान्हा' का भी प्रकाशन किया है।

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बोर्ड ने शेयरों के 1:10 के अनुपात में विभाजन को मंजूरी दी

इंदौर, एजेंसी। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) सेवाओं में अग्रणी कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एचएमपीएल) (बीएसईः 532467) ने आज घोषणा की है कि कंपनी के शेयरों का विभाजन 1:10 के अनुपात में किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक शेयर को दस नए शेयरों में बदल दिया जाएगा। यह निर्णय कंपनी के बोर्ड की 26 जुलाई 2024 को हुई बैठक में लिया गया है। इस बदलाव को अंतिम रूप देने के लिए शेयरधारकों और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की जरूरत होगी। इससे पहले इस साल, कंपनी के बोर्ड ने 4860 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी थी। यह राशि पूरी तरह से परिवर्तनीय वारंट्स के जरिए जुटाई जाएगी, जिसकी कीमत 300 रुपये प्रति वारंट होगी। इस प्रस्ताव को भी शेयरधारकों और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की जरूरत है। इस धनराशि का इस्तेमाल करने के लिए एक फंड जुटाने वाली समिति भी बनाई जाएगी। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) सेवाओं के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कंपनी ने इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाएं हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एचएमपीएल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इन परियोजनाओं को ईपीसी और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) दोनों तरीकों से पूरा किया गया।

आईआईएम संबलपुर के दिल्ली कैम्पस में गरिमापूर्ण समारोह के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के दूसरे एमबीए बैच की शुरुआत

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक आईआईएम संबलपुर ने अपने दिल्ली परिसर में वसंत कुंज के आईएसआईडी में वर्किंग प्रोफेशनल्स के दूसरे एमबीए बैच का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। एनएसई अकादमी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम आज के प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में उद्योग-केंद्रित शिक्षा प्रदान करने और नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमबीए का यह दूसरा बैच विविधता और अनुभव के एक बेहतरीन संयोजन के रूप में सामने आता है, जिसमें विद्यार्थियों की औसत आयु 31 वर्ष है और जिसमें 75 फीसदी छात्र और 25 प्रतिशत छात्राएं हैं। औसतन 5.5 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स

इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी और सर्विसेज, मैन्यूफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फाइनेंस और कंसल्टिंग और अन्य विविध उद्योगों से आते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन कंपनियों से आते हैं, उनमें ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज, आईबीएम इंडिया, एडोब और भारती एयरटेल जैसी ग्लोबल कंपनियां शामिल हैं। यह एमबीए प्रोग्राम डेटा साइंस और प्रॉडक्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ इनोवेशन और स्टार्टअप में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। समारोह की शुरुआत आईआईएम संबलपुर के डायरेक्टर प्रो. महादेव जायसवाल के संबोधन से हुई, जिन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों का खुलासा किया और कहा, ''हम अपने दिल्ली कैम्पस में वर्किंग प्रोफेशनल्स के दूसरे एमबीए बैच का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं।

भारत में गैलेक्सी एआई पावर्ड गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और जेड फ्लिप6 को शानदार रिस्पॉन्स मिला

गुरुग्राम, एजेंसी। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, सैमसंग ने आज घोषणा की कि जो ग्राहक भारत में गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और गैलेक्सी जेड फ्लिप6 के लिए प्री-बुकिंग कर चुके हैं, उन्हें समय से पहले डिलीवरी मिलेगी। गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और गैलेक्सी जेड फ्लिप6 ने पिछले फोल्डेबल

फोन्स की तुलना में सिर्फ 24 घंटों में 40 प्रतिशत ज्यादा प्री-ऑर्डर हासिल किए हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और जेड फ्लिप6 के लिए प्री-ऑर्डर भारत और बाकी दुनिया में 10 जुलाई को शुरू हुए। ये नए स्मार्टफोन 24 जुलाई, 2024 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, साथ ही हाल ही में लॉन्च किए गए अन्य डिवाइस - गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा, गैलेक्सी वॉच7, गैलेक्सी बड्स3 प्रो और गैलेक्सी बड्स3 भी मिलेंगे। सैमसंग इंडिया के एमएक्स बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजू पुलन ने कहा, ''हम भारत में अपने नए फोल्डेबल्स - गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और गैलेक्सी जेड फ्लिप6 को लेकर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया से बहुत खुश हैं। प्री-ऑर्डर में 1.4 गुना वृद्धि से पता चलता है कि भारतीय उपभोक्ता नई तकनीक को तेजी से अपनाने वाले हैं। ये नए फोल्डेबल स्मार्टफोन, जो अब छठी पीढ़ी में हैं, गैलेक्सी एआई के नए युग की शुरुआत करते हैं और संचार, उत्पादकता और रचनात्मकता में मोबाइल अनुभवों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड6 और गैलेक्सी जेड फ्लिप6 की सफलता से हमें भारत में अपने प्रीमियम सेगमेंट में नेतृत्व को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए शानदार परिणाम घोषित किए

अहमदाबाद एजेंसी। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड ग्रुप मंगलम का कृषि व्यवसाय, ने 25 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। तिमाही वित्तीय हाइलाइट्स (समेकित): परिचालन से राजस्वः 679.97 करोड़ रुपये (110 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) एबिटा 15.52 करोड़ रुपये (30 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) कर पूर्व लाभ : 7.69 करोड़ रुपये (73 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) कर पश्चात लाभ : 6.01 करोड़ रुपये (31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) प्रति शेयर आय (डाइल्यूटेड): 0.41 रुपये 30 जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए, कंपनी ने परिचालन से 679.97 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 110 प्रतिशत अधिक है। एबिटा (अन्य आय सहित) में 30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की पहली तिमाही के 11.97 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष की पहली तिमाही में 15.52 करोड़ रुपये हो गया। कर पूर्व लाभ में 73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 7.69 करोड़ रुपये रहा। कर पश्चात लाभ में 31 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की पहली तिमाही के 4.58 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष की पहली तिमाही में 6.01 करोड़ रुपये हो गया। पिछले कुछ समय में, कंपनी ने अरंडी के तेल के कारोबार में बड़ी सफलता पाई है। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड की खेती के व्यापार में यह सबसे अहम हिस्सा है और कंपनी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अरंडी का तेल बनाने और बेचने पर ध्यान देकर, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड इस काम में सबसे आगे आ गई है।

रुशिल डेकोर लिमिटेड ने ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में विस्तार किया

अहमदाबाद, एजेंसी। इको-फ्रेंडली एमडीएफ, लैमिनेट्स, पीवीसी और डब्ल्यूपीसी की लीडिंग मैन्युफैक्चरर, रुशिल डेकोर लिमिटेड (बीएसईः 533470, एनएसई) नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है, जो इसकी ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। रुशिल डेकोर पहले से ही 50 से अधिक देशों में पहुंच रहा है, इसका लक्ष्य लैमिनेट्स और एमडीएफ के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक का लाभ उठाना है। यह स्ट्रेटिजिक मूव 6 से 9 अगस्त, 2024 तक अटलांटा में इंटरनेशनल वुडवर्किंग फेयर में कंपनी की भागीदारी के साथ मेल खाता है। इंटरनेशनल वुडवर्किंग फेयर अटलांटा वुडवर्किंग टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के लिए उत्तरी अमेरिका के मुख्य ट्रेड शो और कॉन्फ्रेंस के रूप में प्रसिद्ध है, जो इंडस्ट्री लीडर्स और दुनिया भर से प्रोफेशनल्स को आकर्षित करता है रुशिल डेकोर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रुशिल ठक्कर ने आशावाद व्यक्त किया और कहा कि, इंटरनेशनल वुडवर्किंग फेयर अटलांटा में हमारी कंपनी का पार्टिसिपेशन, उत्तरी अमेरिका में एक मज़बूत उपस्थिति स्थापित करने, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और हाई-क्वॉलिटी प्रोडक्ट पेशकशों में हमारी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हम नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में प्रवेश करने के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हैं, अरबों डॉलर के लकड़ी के पैनल मार्केट द्वारा पेश की जाने वाली संभावनाओं और लोकल और ग्लोबल दोनों ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज़ सस्टेनेबल, ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स देने के प्रति हमारे समर्पण पर ज़ोर देते हैं।

टाटा इंटरनेशनल अगले चार साल में अपने कुल उत्पादन में वहनीय चमड़े का योगदान बढ़ाकर करेगी 50 प्रतिशत

सीएलआरआई के साथ पेटेंट टेक्नोलॉजी के जरिये लॉन्च किया इको फ्रेंडली-फीनिक्स लेदर

मुंबई, एजेंसी। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा, टाटा इंटरनेशनल ने अपने अर्थकेयर0 लेदर रेंज के तहत पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, फीनिक्स लेदर के लॉन्च के साथ वहनीय प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएलआरआई), चेन्नई के साथ पेटेंट गठजोड़ के ज़रिये विकसित, फीनिक्स लेदर, वहनीय चमड़ा टेक्नोलॉजी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

टाटा इंटरनेशनल में फिनिश्ड लेदर बिज़नेस विभाग के बिजनेस हेड, श्री पी. राजशेखरन ने कहा, टाटा इंटरनेशनल की अर्थकेयर0 लेदर रेंज का उद्देश्य है, चमड़ा उद्योग के वहनीय विकास का नेतृत्व करना। कोविड के बाद कम मांग के बावजूद, अब यूएसए, चीन और यूरोप जैसे प्रमुख बाज़ारों से दिलचस्पी बढ़ने के बीच उल्लेखनीय रिकवरी दर्ज हो रही है। टाटा इंटरनेशनल, भारत में चमड़े और चमड़े के उत्पादों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। हम वहनीय और जैव-आधारित (बायो बेस्ड) चमड़े के बारे में आशावादी हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान अर्थकेयर0 चमड़े का योगदान हमारे कुल उत्पादन का 27 प्रतिशत था और हम अगले 4 साल में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना बना रहे हैं।

एसबीआई म्यूचुअल फंडव्दारा निवेशकों के लिए एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड योजना

मुंबई, एजेंसी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप निवेशकों के लिए एक नया फंड एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का आरंभ किया है । यह फंड मुख्यतः ओपन-एंडेड श्रेणी में है । नई रणनीतियों और अवधारणाओं को भुनाने की चाहत रखने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित विकल्पोमें निवेश करके निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना, यह इस फंड का मुख्य निवेश उद्देश्य है । हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि, योजना के निवेश उद्देश्य पूरे होंगे । इस फंड के लिए निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क इंडेक्स होगा ।

नए फंड के लॉन्च पर बोलते हुए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शमशेर सिंह ने कहा, आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विकसित भारत का केंद्र बिंदु इनोवेशन बन गया है । स्टार्ट अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया स्टैक जैसी पहलों के माध्यम से स्कूल से लेकर उद्योग तक नवाचार की संस्कृति और मजबूत बनाना यह सरकार का लक्ष्य है । एक बड़े उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ एक संपन्न स्टार्टअप और निवेश अर्थव्यवस्था वर्तमान में हमारे देश को नवाचार क्षितिज पर एक नेता के रूप में उभरने के लिए कई अनुकूल कारक प्रदान कर रही है । प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए लगातार नवाचार कर रहे और ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले तत्वों में मूल्य जोड़ने के लिए अलग तरीके से काम कर रहे कंपनियों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक शानदार अवसर है । एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक और सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. डी. पी. सिंह ने कहा, हमने ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा, मीडिया और मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ई-कॉमर्स और उद्योग जैसे क्षेत्रों में नवाचार द्वारा संचालित कई बदलावों और उथल-पुथल का अनुभव किया है ।

लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड बोर्ड ने इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट को मंजूरी दी

मुंबई एजेंसी। रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड (बीएसई- 540952, एनएसई- रू) ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने 1,48,340 वारंट्स को 1 रुपये प्रति फेस वैल्यू के 14,83,400 इक्विटी शेयर्स में बदलने की मंजूरी दे दी है। 5 अक्टूबर, 2023 को प्रेफरेंशिएल बेसिस पर आवंटित 10,38,371 वारंट्स में से 2.25 करोड़ रुपये का जमा अमाउंट ऑर्चर्ड रोड प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ। हाल ही में कंपनी ने 2,47,230 वारंट्स को 1 रुपये प्रति फेस वैल्यू के 2,47,23,00 इक्विटी शेयर्स में बदलने की मंजूरी दे दी है।

उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वैल्स लिमिटेड का आईपीओ आज खुलेगा

मुंबई, एजेंसी। भारत के ज्वेलरी बाजार की एक विशिष्ट ब्रांड, उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वैल्स लिमिटेड ने 31 जुलाई 2024 को इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) के साथ पब्लिक में जाने की अपनी योजना की घोषणा की है. कंपनी का इरादा अपर बैंड पर 69.50 करोड़ एकत्र करने का है. कंपनी के शेयर्स सेट एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर लिस्ट होंगे.इश्यू से प्राप्त होने वाली शुद्ध धनराशि का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी करने और आम कॉर्पोरेट कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा. एंकर पोर्शन की बिडिंग 30 जुलाई 2024 को खुलेगी. रिटेल अभिदान के लिए इश्यू 31 जुलाई 2024 को खुल रहा है और 2 अगस्त 2024 को बंद होगा. इश्यू की लीड मैनेजर चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है. इश्यू की रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है.

उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वैल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर, श्री पंकजकुमार एच. जगावत ने कहा, हम हमारे आगामी आईपीओ की घोषणा करते हुए अति हर्षित हैं. किफायती लग्जरी ज्वेलरी की बढ़ती मांग से उत्सव निरंतर सफलता के लिए बेहतर स्थिति में है. हमारी आधुनिक उत्पादन सुविधाएं, कुशल श्रम तथा व्यवस्थापन सुविज्ञता ने हमारे उच्च उत्पादकता को आगे बढ़ाया है . हम टॉप क्वालिटी ज्वेलरी की डिलीवरी करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो युवाओं की पसंद पूरी करने के साथ दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त है .इनोवेशन के प्रति हमारा समर्पण 15 कैड डिजाइनर की हमारी टीम का प्रमाण है, जो बाजार के रुझान से आगे बने रहने के लिए हर महीने लगभग 400 नई डिजाइन का निर्माण करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में ऑपरेशन की हमारी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी है।

शैक्षणिक सत्र से पूर्व मेडिकल छात्रों के लिए हिन्दी में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

चिकित्सा शिक्षा की कुल 20 पुस्तकों में 15 वर्तमान में उपलब्ध

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्य-सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा की। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व चिकित्सा शिक्षा सभी वर्षों की पाठ्यपुस्तकों की हिन्दी भाषा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उप-मुख्यमंत्री ने वर्षवार और विषयवार पाठ्यपुस्तकों के लिप्यंतरण कार्य की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने हिन्दी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे छात्रों के फीडबैक के संबंध में जानकारी

प्राप्त की। लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का लाभ ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न वर्षों की कुल 20 पुस्तकों में से 15 पुस्तकों का लिप्यंतरण किया जा चुका है और ये शासकीय मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। साथ ही शेष 5 पाठ्यपुस्तकों का लिप्यंतरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिनके मूल्यांकन के उपरांत प्रिंटिंग की कार्यवाही 10 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मो. सुलेमान, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण कुमार पिथोड़े, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ अरुण श्रीवास्तव, प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा विभाग एवं राज्य नोडल अधिकारी हिन्दी प्रकोष्ठ डॉ लोकेंद्र दवे, उप कुलसचिव एवं राज्य समन्वयक हिन्दी प्रकोष्ठ श्रीमती अमृता बाजपेयी, सलाहकार हिन्दी प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रागिता अग्निहोत्री सहित विभिन्न पुस्तकों के लिप्यंतरण में कार्य कर रहे प्रोफेसर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जन-औषधि केंद्रों के लाभ के प्रति आमजन को करें जागरूक: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जन-औषधि केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और जागरूकता लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन-औषधि मेला लगाये जाने की व्यवस्था करें ताकि इच्छुक व्यक्ति आगे आयें साथ ही आमजन को भी जन-औषधि केंद्रों की सुविधाओं और लाभों के प्रति जागरूक किया जाये। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 412 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में पूरे देश में 'जन औषधि योजना' शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आमजन में इस बात की जागरूकता लाना कि दवाइयों की उच्च कीमत उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाएँ गुणवत्ता परीक्षण की भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार हैं एवं उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाता है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मो. सुलेमान, एमडी एमपीपीएचएससीएल डॉ पंकज जैन, कंट्रोलर एफडीए श्री मयंक अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अंगदान/प्रत्यारोपण में इमर्जिंग स्टेट कैटेगरी में मध्यप्रदेश होगा पुरस्कृत

भोपाल। मध्यप्रदेश को 14वें भारतीय अंगदान दिवस (आईओडीडी) 3 अगस्त 2024 को अंगदान/प्रत्यारोपण में उभरते राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा नई दिल्ली में मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करेंगे । उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समस्त विभागीय अधिकारियों और जागरूक नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि उप-मुख्यमंत्री शुक्ल अंगदान प्रक्रिया को सहज और जन-सुविधाजनक बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं। अंगदान जीवनदान है: उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि अंगदान जीवनदान है।अंगदान एक महान सेवा है। दान किया गया एक अंग किसी के जीवन को नई उम्मीद और खुशियाँ दे सकता है। अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को जीवन का दूसरा मौका मिल सकता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिससे हम एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग स्वेच्छा से मानवता को सशक्त करने वाले इस पुण्य कार्य के लिए आगे आयें।

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल से ऊर्जा मंत्री तोमर ने सौजन्य भेंट की

भोपाल। उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में ऊर्जा मंत्री श्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सौजन्य भेंट की। उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों में उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से चर्चा की।

भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित कर प्रभात झा को किया याद

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की श्रद्धांजलि सभा मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गयी। जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्री झा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको याद किया।

भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भोपाल जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं प्रभात जी के पास पहुंचा और उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम सबसे छोटे उम्र के जिला अध्यक्ष बनें हो, सभी को साथ लेकर चलना होगा। अपनी हिम्मत को कभी हारने मत देना। नगर निगम चुनाव के दौरान श्री झा ने कहा कि मेहनती कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, यह जरूर जीतकर आयेंगे। पचौरी ने

कहा कि प्रभात झा जी ने हमेशा आदर्श कार्यकर्ता के रूप में जीवन बिताया। लोक कल्याण और जनता के हित के लिये सदैव कार्य करते रहे। प्रभात जी का मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को हमेशा मिलता रहा है। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

महापौर मालती राय ने कहा कि वर्ष 1994 में प्रभात झा मीडिया प्रभारी रहते हुए मैं जिला महामंत्री थी। मुझसे प्रभात जी ने कहा था कि आप जैसे लोग नगर निगम में होने चाहिए। उनके बताए मार्ग पर चलकर कई वर्षों बाद आज मैं महापौर के पद पर हूं। उ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। गहन दु:ख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें।

जिला महामंत्री रविंद्र यति, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक सैनी एवं सतीश विश्वकर्मा ने भी स्वर्गीय प्रभात को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए याद किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पार्षद सहित कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

सांसद आलोक शर्मा ने जहरीले कचरे के निष्पादन के संबंध में सवाल उठाया

भोपाल। सांसद आलोक शर्मा द्वारा यूनियन कार्बाइड के प्रतियुक्त कारखाने के अंदर एक वेयरहाउस में पड़े 336 MT जहरीले कचरे के निष्पादन के सम्बन्ध में लोकसभा में सवाल उठाया। गैस पीड़ित संगठन सांसद के इस कदम का स्वागत करते है की कई दशकों बाद भोपाल के सांसद ने विश्व की भीषणतम औद्योगिक हादसे के बारे में कम से कम सवाल तो उठाया।

सांसद अगर वाकई में कारखाने की सफाई कराना और स्मारक का निर्माण कराना चाहते है तो उसके लिए कारखाने के अंदर 21 गड्डो में दबे जहरीले कचरे और कारखाने के पीछे बने कारबाईड के जहरीले तलाबो में पड़ा हुआ हजारो टन जहरीला कचरे का आकलन और निष्पादन करने पर ही किसी समार्क का निर्माण हो सकता है. 336 MT तो पूरे कचरे का 1 प्रतिशत भी नही है और जो कचरा बाहर और अंदर दबा है उसी की वजह से अब तक 42 बस्तियो का भूजल अत्यंत जहरीले रसायनों से

प्रदूषित हुआ है. आशा है कि सांसद जी इस बात का भी संज्ञान लेंगे की इस कचरे की सफाई का पैसा उन्ही कम्पनियो (यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल) से आना चाहिए जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है और ना की हमारे देश की जनता के पैसे से. भारत सरकार ने 2010 में कम्पनी से 350 करोड़ की राशि इसी कचरे की सफाई के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मांगी थी पर आज तक उस राशि को लेने के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम नही उठाया है. आशा है कि सांसद जी इसके बारे में भी प्रश्न उठाएगे और यह सुनिश्चित करेंगे की सम्पूर्ण कचरे की सफाई हो एवं मिट्टी पानी की सफाई का भुगतान दोषी कंपनियां करे।

धान परिवहन एवं अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी निलंबित

किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी: गोविंद सिंह राजपूत

खाद्य मंत्री के निर्देश पर गड़बड़ी करने वालों पर प्रदेश भर में कार्रवाई जारी

भोपाल । रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान के परिवहन एवं मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गैरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये थे। श्री राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि जांच दल द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में श्री पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

ज्योति सिंह राजपूत क्षत्रिय करणी सेना की संभागी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनी

भोपाल। ज्योति सिंह राजपूत को राजपूत क्षत्रिय करणी सेना की संभागीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का दायित्व मिला

यह जिम्मेदारी उनकी समाज सेवा को देखते हुए संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मंजीत कीर्तिराज सिंह दी वही ज्योति सिंह राजपूत ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने दायित्व को जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाऊंगी और संगठन को उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करूंगी उनकी इस नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

क्षत्रिय करणी सेना की बैठक संपन्न

भोपाल। क्षत्रिय करणी सेना की प्रदेश स्तरीय बैठक राजवीर पैलेस, भोपाल इंदौर बाईपास में संपन्न हुई। संभाग अध्यक्ष वंदना ठाकुर ने ने बताया कि विशेष रूप से कार्यक्रम में संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत मनजीत कीर्तिराज मिटावल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व म.प्र अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ) प्रदेश अध्यक्ष (क्षत्रिय करणी सेना परिवार) इंदल सिंह राणा इंदल सिंह घराना आदि संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की भोपाल जिला अध्यक्ष आशु सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।

दमोह में चार लड़कियों के गुम होने से प्रदेश सरकार के नारी सुरक्षा के दावे की पोल खुली: विभा पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश अब लड़कियों और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यादव सरकार का नारी सम्मान और महिला सुरक्षा का दावा खोखला है। इसकी ताजी मिसाल सोमवार को दमोह से गुम हुई कॉलेज की चार छात्राएं हैं, जिन्हें पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। ये सरकार के लचर कानून सिस्टम की कलई खोलता है। इस घटना के पहले सागर जिले से 245 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। विभा पटेल ने कहा कि दमोह पुलिस की कार्यप्रणाली से पता चलता है कि पुलिस लड़कियों के गुम होने के मामले पंजीबद्ध कर रही है, लेकिन तलाशने के नाम पर महज तफरी कार्रवाई कर इतिश्री हो रही है। प्रदेश सरकार भले ही महिला सुरक्षा के नाम पर ढोल पीट रही हो, लेकिन हकीकत सरकार के दावों से कोसों दूर है। यहीं स्थिति रही तो बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं

मजबूर होकर घर से बाहर निकलना ही छोड़ देंगी।

श्रीमती पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला अपराध के मामले में मध्य प्रदेश, देश की राजधानी बन गया है। ग्वालियर में 214 महिलाएं पिछले एक माह से ज्यादा समय से लापता हैं, उसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ 3 मामले ही पंजीबद्ध किए हैं। इंदौर में 479 महिलाएं एक माह से ज्यादा समय से लापता हैं, परंतु पुलिस ने सिर्फ 15 प्रकरण दर्ज किए। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में तो 135 महिलाएं एक माह से ज्यादा समय से गायब होने के बाद भी एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, ये आधिकारिक आकंड़े सरकार की तत्परता को बयां करने के लिए काफी है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति और सास की जमानत निरस्त

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति और सास की जमानत न्यायालय ने निरस्त कर दी है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति और सास की जमानत निरस्त संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि 30/07/2024 न्यायालय विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यानयाधीश (ओ.ए.डब्लूअ.) के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति निखिल दुबे एवं सास आशा दुबे की अग्रिम जमानत निरस्त की गई । उक्तल प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तएव द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का विवरण: 9-07-2024 को डॉक्ट्र, एम्स अस्पताल द्वारा थाना गोविंदपुरा में मृतिका पूजा थापक द्वारा फांसी लगाने से इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना पर मर्ग कायमी कर मर्ग जाचं के दौरान मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया तथा मर्ग जांच मृतिका के पिता, मां, भाई, एवं बहन के कथन लेख किये गये। मृतिका के पिता ने अपने कथनों में बताया कि उन्होनें अपनी बेटी की शादी में 40 लाख रूपये खर्च किये। उसकी बेटी की सास आशा दुबे एवं पति की मांग पर दहेज का सामान एवं परिवार के सदस्यों को ज्वेलरी दी गयी थी और शादी के बाद से ही उनके द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी थी एवं उनकी बेटी पर इंदौर में फ?लेट खरीदने का दबाव बना रहे थे तो दिनांक 19-09-2023 को 22 लाख आरटीजीएस के माध्यम से जमा किये थे साथ ही उसके बेटे ने दिनांक 22/23-01-2022 को 90 हजार रूपये एवं 660000/- रूपये आरोपी निखिल के खाते में ट्रांसफर किये थे। शादी के पश्चात उसकी बेटी द्वारा यह भी बताया गया कि उसकी सारी ज्वेलरी सास ने रख ली थी और कहा था कि पहनने के लिए ज्वैलरी अपने घर से लेकर आओ। उसने मई 2024 के अंतिम सप्ताह में 2 सेट सोने की ज्वेलरी का उसकी बेटी को दिया था और बेटी की सास एवं पति भोपाल में बडे प्लाट की मांग कर रहे थे तथा दोनों उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के एचडीएफसी बैंक के खाते की पासबुक के स्टेटमेंट की सत्यापित प्रति तथा मृतिका के भाई से मृतिका का एप्पल आईफोन मोबाईल, व्हाट्सअप स्कीनशाट की छायाप्रतियां तथा भाई के एसडीएफसी बैंक के स्टेटमेंट की छायाप्रतियां जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। मर्ग जांच में आये सुसंगत तथ्यों से मृतिका के पति नितिन दुबे एवं सास आशा दुबे के विरूद्ध धारा 80, 85, 108 एवं धारा-3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन अंकित किय गये तथा उनके धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत कथन न्या यालय में कराये गये।

एम्स के छात्रों ने किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन नीदरलैंड्स का दौरा

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह संकाय और छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और ज्ञान-साझाकरण की संस्कृति को सदैव बढ़ावा देते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में, एम्स भोपाल ने विभिन्न शैक्षणिक मंचों पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में एम्स भोपाल के एमबीबीएस 2020 और 2021 बैच के चार छात्रों ने 10 जुलाई से 17 जुलाई तक नीदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन द्वारा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ग्रोनिंगन (यूएमसीजी) के सहयोग से आयोजित समर स्कूल ऑफ ऑन्कोलॉजी में भाग लिया। चयनित छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को देखते हुए पूर्ण छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी।

इस दौरान, छात्रों ने टांके लगाने की तकनीक और लेप्रोस्कोपिक अभ्यास पर उन्नत कार्यशालाओं में भाग लिया, जहाँ उन्हें शल्य चिकित्सा कौशल को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कैंसर के विभिन्न प्रकारों और उपचारों पर व्यापक व्याख्यानों में भी भाग लिया, जिससे उन्हें ऑन्कोलॉजी में नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी मिली। अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करने से उन्हें भविष्य के कैंसर उपचारों की भी जानकारी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा, छात्रों ने रोगियों से बातचीत कर डच चिकित्सा प्रणाली का अवलोकन किया।

नीदरलैंड्स से लौटकर छात्रों ने एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपने दौरे के अनुभवों से अवगत कराया। प्रो. सिंह ने छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की और उन्हें हार्दिक बधाई दी। कार्यपालक निदेशक ने कहा, इस तरह के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि एम्स भोपाल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाती है। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और हमें विश्वास है कि वे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

बाल रोग विभाग ने मनाया ओआरएस दिवस

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ) अजय सिंह के नेतृत्वग में बाल रोग विभाग द्वारा सोमवार को ओआरएस दिवस मनाया गया। प्रो. सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी बातों को अपनाकर हम भावी पीढ़ी को सशक्ता और स्व।स्थड रख सकते हैं। साथ ही बच्चों की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्याीन देने की आवश्यसकता है क्यों कि गंदगी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। दरअसल 25-31 जुलाई के मध्य ओआरएस सप्ताह के रूप में और 29 जुलाई को ओआरएस दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चों में निर्जलीकरण से बचाव के लिए इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (द्धक्क) और स्मार्ट यूनिट, बालरोग विभाग के सहयोग से विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में डायरिया से संबंधित जागरूकता फैलाना और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट) के महत्व को समझाना था।

स म्पा द की य

जनगणना और जातिगत आधार..

संसद में जातिगत जनगणना का मामला फिर से उठने लगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामला उठाया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति को लेकर फब्ती कसना शुरू कर दिया। हालांकि यह बहस गलत दिशा में जाती दिख रही है, लेकिन जनगणना तो होना ही है। इसमें यदि जाति का मुद्दा शामिल कर लिया जाए तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज टिकट वितरण से लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति तक राजनीतिक दलों में अधिकांश जातिगत आधार पर ही होती है। फिर जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है?

जनगणना की बात करें तो भारत में उन्नीसवीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था। उसके पीछे संभवत: इस विशाल देश पर शासन करना आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन बाद में दशकीय-जनगणना इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और कई विद्वानों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जनगणना के आंकड़ों से ही हमें लगभग 50 साल पहले भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या का पता चला, लड़कों की तुलना में लड़कियों की उच्च मृत्यु दर। 1881 से 2011 तक, हर दस साल में प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में जनगणना की जाती थी। इसके अनुसार अगली जनगणना 2021 में होनी थी।

कोविड संकट ने केंद्र सरकार को जनगणना स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया। तब से तीन साल बीत चुके हैं, और अगली जनगणना के लिए अभी भी सक्रिय तैयारी का कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि सौ से अधिक देशों ने कोविड के दौरान या उसके बाद जनगणना की है। जनगणना में देरी से स्वाभाविक तौर पर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे कि हम 2011 के बाद से साक्षरता की प्रगति का आकलन करने में असमर्थ हैं। कोविड के दौरान लगभग दो साल स्कूल बंद रहे, हमें यह जानने की जरूरत है कि इससे बच्चों की पढ़ने-लिखने की क्षमता पर क्या असर पड़ा। जनगणना कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे, यह प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी का स्रोत है। राज्यों के बीच कर-राजस्व के आवंटन के लिए इसकी जरूरत है। इसका उपयोग कई सर्वेक्षणों के लिए एक रूपरेखा के रूप में किया जाता है। कई मुद्दों पर तो अंदाज से ही काम चलाया जा रहा है।

जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता का एक और कारण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का न्यूनतम कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 2013 में अधिनियम के लागू होने के बाद ये अनुपात 2011 की आबादी पर लागू किए गए और 80 करोड़ व्यक्ति सस्ते अनाज के हकदार बने। यदि वही अनुपात वर्तमान आबादी पर लागू किए जाते तो शायद आज अन्य 10 करोड़ लोग सस्ते अनाज से लाभान्वित होते। आज लगभग 10 करोड़ लोग जन-वितरण प्रणाली से वंचित हैं, क्योंकि सरकार पुरानी जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रही है।

जनगणना के साथ ही परिसीमन भी होना है। लेकिन बिना जनगणना के परिसीमन का कोई औचित्य ही नहीं होगा। भारत के उत्तरी राज्यों की आबादी दक्षिणी राज्यों की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। इसलिए आबादी में उत्तरी राज्यों का हिस्सा आज 1973 की तुलना में ज्यादा है। हालांकि आज की परिस्थितियों में परिसीमन सत्ता पर काबिज भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में सीटों की संख्या दक्षिण के मुकाबले काफी अधिक बढ़ जाएंगी और वहां भाजपा का वोट प्रतिशत अधिक है।

अब आते हैं जातिगत जनगणना पर। बिहार का मामला अभी सामने आया। हालांकि वहां की जातिगत जनगणना से कई जातियों को नुकसान भी होने की आशंका है, लेकिन हमें इसका सही आंकड़ा तो मालूम होना ही चाहिए कि कहां किस जाति के कितने लोग रहते हैं। देखा जाए तो भले ही कई राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि वे जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करतीं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जब टिकट बांटे जाते हैं, तो पूरे भले ही नहीं, लेकिन जातिगत वोटरों का अनुपात तो देखा ही जाता है। औसत भी देखा जाता है। और फिर जातिगत संतुलन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

विधानसभा और लोकसभा सीटों का आरक्षण भी अनुसूचित जाति, जनजाति के आधार पर जब होता है, तो इसमें सभी जातियों की आबादी सार्वजनिक करने में क्या समस्या है? संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर भले ही बहस गलत दिशा में चली गई हो, लेकिन जब पूरी राजनीति जाति आधारित हो रही है, तो जनगणना के दौरान जाति की आबादी स्पष्ट करने में क्या हर्ज है? संसद की बहस तो गलत दिशा में जाती दिख रही है। जो सवाल केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष से पूछ रहे हैं, यदि यही सवाल कांग्रेस सांसद पूछते तो निश्चित तौर पर दर्जनों एफआईआर दर्ज करवा दी जातीं और अदालतों में याचिकाओं की कतार लग जाती। यह उचित बहस नहीं कही जा सकती। लेकिन जनगणना का मौका आ गया है, तो जनगणना का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

जयंती: अब किस दुनिया में जिएं प्रेमचंद के झूरी काछी और हीरा-मोती

जयराम शुक्ल

आज प्रेमचन्द जयंती है। आज के दिन प्रेमचंद बड़ी शिद्दत से याद किए जाते हैं। हमारे यहां एक रिवाज है जिसे न मानना हो उसको पूजना शुरु कर दो। नेताओं ने ऐसे ही गाँधी को पूजना शुरू कर दिया। फोटो को चौखटे में मढ दिया ताकि वहीं कैद रहें निकले नहीं। साहित्यकारों ने ऐसे ही प्रेमचंद को बना दिया।

प्रेमचन्द का समाज अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के पंच परमेश्वर का समाज था, मुँहदेखी और पक्षपात से सर्वथा अलग। आज साहित्यकारिता में चारण-भाँटों या वैचारिक विरोधियों के साथ शाब्दिक व्यभिचारियों का दौर है। बीच का वर्ग सुविधाश्रयी है।

प्रेमचन्द तुलसी की तरह सहज, सरल और तरल थे। हिन्दी जगत में सबसे ज्यादा पढे जानेवाले साहित्य सर्जक। जनजीवन के सबसे ज्यादा करीब और संवेदनशील।

तुलसी ने कागभुशुण्डि -गरुड़ (कौव्वा और बाज) से रामकथा गवा दी, तो प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में हीरा..मोती नाम के बैलों से जीवनमूल्यों की स्थापना और मुक्ति के संघर्ष का संदेश दिया।

इन दिनों प्रेमचंद की यह मर्मस्पर्शी कहानी रह रह कर टीसती सी है। यह कहानी पिछली सदी के तीस के दशक की थी। प्रेमचंद को पूंजीवाद के विस्तार और आक्टोपसी अर्थसंस्कृति के धमक की आहट तो थी लेकिन भारतमाता की ग्राम्यवासिनी अर्थव्यवस्था से हीरा मोती को झूरी काछी की थान से बूचडख़ाने तक का सफर करना पड़ेगा इसकी शायद कल्पना भी नहीं थी।

आज देश में गोरक्षा को लेकर उन्माद है। लेकिन ऐसी स्थित क्यों और कैसे बनी व विकल्प क्या है इसपर विचार करने कोई तैय्यार नहीं है। प्रेमचंद के अलगू चौधरी व जुम्मन शेख वाले समाज मे इस उन्माद ने मोब लीचिंग का रूप ले लिया है।

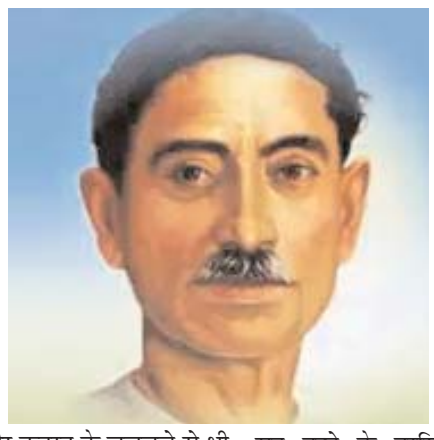

इस देश में भांग के नशे के तरंग की भाँति शब्दों का भी ज्वार भाटा आता है। आवारा लहरें गरीब, मासूम और मजलूम लोगों बहा ले जाती हैं। ऐसा दौर कुदरत के जलजले से भी खतरनाक होता है। पुराणकथाओं में जब जनजीवन पर संकट आता था तब .भूमि विचारी गो तनुधारी.. ईश्वर से फरियाद करने जाती थी। आज गाय को हिन्सा का निमित्त बना दिया गया। गाय और गोवंश को इस दशा तक पहुंचाने वाले कसाई कौन हैं.?

गाय और गोवंश युगों से हमारी अर्थव्यवस्था और लोकजीवन की धुरी रहा है। भगवान् कृष्ण को इसीलिये गोपाल बनना पड़ा था। आज हमने घर में मंदिर बनाकर गोपालजी की प्राणप्रतिष्ठा तो कर ली और ज्यादा धार्मिक हो गए और गोमाता को सडक़ पर विष्ठा, पन्नी खाकर मरने के लिए और सरहंगों, गुन्डों को गाय के नामपर गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया।

गाय और गोवंश को हमारे नीति निर्धारकों ने योजनाबद्ध तरीके से बाहर किया और हमने इसका बढचढकर समर्थन किया। गांधी जी ने ग्रामस्वराज्य की अवधारणा दी। गांव के संसाधनों के वैग्यानिक कौशल के विकास के पक्षधर थे। उनको यह चिंता थी कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का माडल गावों को गुलाम बना देगा। यूरोपीय माडल मशीन की धुरी पर टिका था जिसमें संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी।

हमने गांधी को सिर्फ पूजा उनकी सीख और नसीहतों को तिलांजलि देदी। नेहरू के फोकस में शहरी और मशीनीकृत अर्थव्यवस्था का माडल था। ग्राम-सुराज की अवधारणा को धीमाजहर देकर मारा गया। हरितक्रांति और फिर सन् नब्बे के नरसिंह राव-मनमोहन माडल ने ग्रामस्वराज्य की अर्थी उठाने की दिशा में कदम बढा दिया।

हमारे पारंपरिक कौशल और खेती के पुश्तैनी ग्यान को डंकल जैसे ग्यानियों ने खा लिया। खेतों का दोहन नहीं शोषण शुरू हो गया। गाय बैल खेती से खारिज कर वहां ट्रैक्टर तैनात कर दिए गए।

यह सही है कि हमारे खेतों में इतना अन्न नहीं उपजता था पहले पर इतना तो उपजता ही था कि किसानों का गुजारा चल जाता था। देश ने सतसठ अरसठ का अकाल भी देखा पर किसानों ने ऐसी आत्महत्याएं नहीं कीं।

आज खेती गुलाम होगयी है और उसके घटक अप्रसांगिक। इसकी सबसे ज्यादा मार उन मूक पशुओं पर पड़ी है जो किसानों के हमदम थे। गाय को लेकर हल्ला मचाने वाले विकल्प की बात नहीं करते।

निश्चित ही गाय हमारी पवित्र आस्थाओं के साथ जुड़ी है पर वह ससम्मान कैसे बचे इसकी कार्ययोजना बननी चाहिए और ये धर्मप्राण सरकार बना भी रही होगी। मुश्किल यह है कि बछडों और बैलों का क्या होगा। इनकी तो अब कोई उपयोगिता नहीं।

शंकरजी का नंदी होने के नाते यद्यपि बैल भी एक धार्मिक प्रतीक है पर आस्थाओं में इसका वो दर्जा नहीं जो गाय को प्राप्त है। गाय और गोवंश को बचाना है तो सरकार को ठोस कदम बनाना ही होगा।

एक सुझाव यह भी है कि जिस तरह भारतीय खाद्य निगम बना है वैसे ही..भारतीय गोवंश निगम बनाया जा सकता है। सरकार घाटा सहकर भी खाद्य निगम को संचालित करता है ताकि देशवासियों की खाद्यसुरक्षा के साथ ही समर्थन मूल्य के जरिए किसानों का भी हित संरक्षण कर सके। उसी तरह गोवंश निगम में भी गाय बछड़ों को संरक्षित करने की व्यवस्था हो।

किसान यहां गोवंश बेच सके। गौवंश के उत्पादों, दूध, गोमूत्र, गोबर की उपयोगिता का प्रचार प्रसार हो। रोज पढने को मिलता है कि गौमूत्र में इतने गुण हैं। इसमें सोना चांदी पाया जाता है। गाय का दूध अमृत है तो इसका बाजारीकरण क्यों नहीं हो सकता।

जिस देश में बीस रुपये के बोतलबंद पानी और पाँच रुपये के आलू को अंकल चिप्स में बदलकर अरबों. खरबों रुपये का व्यापार किया जा सकता है तो फिर गोवंश के उत्पाद क्यों नहीं.? आखिर यह धर्मप्राण देश है।

गाय के लिए हम मरने मारने पर उतारू हैं तो उसे बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आज गांधी होते तो अपने ग्राम स्वराज की दुर्दशा देखकर जार जार रोते और प्रेमचंद झूरी काछी के हीरा मोती को बचाने के लिए समूची रचनाधर्मिता दाँव पर लगा देते।

अग्निवीर ,अग्निवीर , अग्निपथ..

राकेश दुबे

कुछ राज्य सरकारों के आश्वासन के बावजूद सेना में अल्पकालिक सेवा के लिए दो वर्ष पूर्व लायी गई अग्निपथ योजना लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है। समय-समय पर सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों ने भी सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती प्रक्रिया की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस योजना के विरोधाभासी मुद्दों को चिन्हित किया है। सवाल इस बात को लेकर उठाये जाते रहे हैं कि कुल अग्निवीरों के पच्चीस प्रतिशत को भी स्थायी कैडर में शामिल किया जाएगा। जबकि देश में प्रचुर संख्या में जनशक्ति उपलब्ध है।

हाल ही में अग्निवीरों के कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की भी चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे ही सेवा मुक्त होने के बाद रंगरूटों के पथ से भटकाव की आशंकाएं बनी रह सकती हैं। कुछ दिग्गजों ने तो यहां तक कहा है कि सेना की पूर्व निर्धारित भर्ती प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

सैन्य वर्ग के भीतर असहमति के अलावा, अग्निपथ योजना राजनीतिक क्षेत्र में भी खासा विवाद का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने न केवल इस योजना का जोरदार ढंग से बचाव किया, बल्कि विपक्षी दलों पर भी भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा व फिट बनाना है। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि यह पहल पेंशन के पैसे बचाने के लिये की गई थी।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस योजना को लगातार निशाने पर लेते रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने इस योजना को रद्द करने की मांग की है।

इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ राजग गठबंधन में शामिल सहयोगी दल जनता दल युनाइटेड ने भी इस योजना की व्यापक समीक्षा की मांग सरकार से की है। निस्संदेह, सरकार अग्निपथ योजना को लेकर उठ रही आवाजों को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती।

आशंका जतायी जा रही है कि सेनाओं से जुड़े मुद्दों पर आम सहमति की कमी सशस्त्र बलों की युद्ध की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। कई भाजपा शासित राज्यों ने पुलिस जैसी वर्दीधारी सेवाओं में नौकरियों में अग्निवीरों के लिये आरक्षण या प्राथमिकता की घोषणा की है, लेकिन ये कदम विरोधियों को चुप कराने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार को इस योजना को लेकर मिल रही प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही योजना से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। f

नस्संदेह, इस मुद्दे पर अड़ियल रवैये की प्रतिक्रिया भविष्य में भी हो सकती है। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा लाये गए तीन कृषि कानूनों के लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन सालभर चले थे। सरकार को गहनता से इस मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों के मनोबल को लेकर कोई प्रयोग नहीं किये जा सकते। देश के सत्ताधीशों को राजनीतिक बड़बोलेपन से परहेज करना चाहिए।

सीआईए और मोसाद के जाल में फंस गए हमास के प्रमुख हानिया

डॉ.ब्रह्मदीप अलूने

जर्मनी के सेनानायक तथा मशहूर सैन्य रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज़ ने अपनी किताब,ऑन वॉर में लिखा है कि शत्रु को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु बाध्य कर देना युद्ध का प्रमुख उद्देश्य है,इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति एवं हिंसा एक साधन है तथा शत्रु को शस्त्र विहीन कर देना ही इस शक्ति एवं हिंसा का एक मात्र लक्ष्य होता है। दरअसल हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर मोसाद और सीआईए ने ईरान को यह संदेश दिया है की ईरान इजराइल और अमेरिका के सैन्य लक्ष्यों में से एक है और इस देश की संप्रभुता और सुरक्षा कभी भी संकट में पड़ सकती है।

इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में हिजबुल्ला की आक्रामकता और ईरान की धमकी से मध्यपूर्व का तनाव चरम पर जाने की आशंकाओं के बीच हानिया का मारा जाना निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन ईरान ने अपने ही देश में हानिया की सुरक्षा में नाकाम रहकर अपने कई प्राक्सी समूहों को भी आशंकित कर दिया है। वहीं हानिया को निशाना बनाने में अमेरिका की वह नीति काम आई है जिसके अनुसार वह ईरान से लगे देशों में दीर्घकालीन संबंधों को बढ़ावा देता रहा है। उसकी यहीं नीति इजराइल की खुफ़िया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफ़िया एजेंसी सीआईए के लिए संजीवनी साबित हो रही है।

ईरान उत्तर में अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से घिरा है। इसके पूर्व में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है जबकि पश्चिम में तुर्की और इराक है। अज़रबैजानी को यूँ तो रूस का करीबी माना जाता है लेकिन वह इजराइल का सामरिक सहयोगी है। अमेरिका और अज़रबैजान के सुरक्षा कितने मजबूत रहे है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की कोसोवो,अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाले मिशनों में अज़रबैजान की सक्रिय भागीदारी रही है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अज़रबैजान को कैस्पियन सागर में अपनी सुरक्षा संरचनाओं को बढ़ाने के लिए 10 मिलियन डॉलर की पेशकश भी की थी। ईरान की सीमा से लगते हुए एक और

देश आर्मेनिया के साथ तो 2023 में अमेरिका ने पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। ईगल पार्टनर 2023 नामक यह अभ्यास आर्मेनिया के सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेने के लिए तैयार करने पर केंद्रित था। इसी प्रकार तुर्कमेनिस्तान अमेरिका के कैस्पियन बेसिन ऊर्जा पहल में एक प्रमुख सहयोगी रहा है जिसे तथाकथित ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है।

मध्य पूर्व में लगभग तिस हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा, इज़राइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से,अमेरिका ने अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में हज़ारों अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं,जिनमें युद्धपोत भी शामिल हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाना जॉर्डन की सीरिया के साथ लगती सीमा के क़रीब है। सीरियाई सीमा के पास उत्तर पूर्वी जॉर्डन के रुकबान नामक जगह पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे है।

मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस कतर में स्थित है,जिसे अल उदीद एयर बेस के रूप में जाना जाता है और इसका निर्माण 1996 में हुआ था। अन्य देश जहां अमेरिका की उपस्थिति है,उनमें बहरीन,कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सीरिया में अमेरिका के करीब नौ सौ सैनिक हैं, जो अल उमर ऑयल फील्ड और अल-शद्दादी जैसे छोटे ठिकानों पर तैनात हैं, जो ज़्यादातर देश के उत्तर-पूर्व में हैं। इराक और जॉर्डन के साथ काउंटी की सीमा के पास एक छोटी चौकी है, जिसे अल तन्फ़ गैरीसन के नाम से जाना जाता है। इराक में ढाई सैनिक हैं, जो यूनियन ढ्ढढ्ढ और ऐन अल असद एयर बेस जैसे ठिकानों पर तैनात हैं।

अमेरिका के प्रमुख सहयोगी जॉर्डन में सैकड़ों अमेरिकी प्रशिक्षक हैं और वे पूरे वर्ष व्यापक अभ्यास करते हैं। कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति सहयोगियों को आश्वस्त करने,प्रशिक्षण देने तथा क्षेत्र में संचालनों में आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए है।

इराक और पूरे क्षेत्र में ईरान का राजनीतिक प्रभाव और मिलिशिया की ताकत पिछले कई सालों से अमेरिका के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय रही है। इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी ईरान के लिए इराक और सीरिया से लेबनान में हथियार ले जाना और भी मुश्किल बना देती है। हिजबुल्लाह पर नियन्त्रण रखने में इससे मदद मिलती है।

दक्षिण पूर्वी सीरिया में अल तन्फ़ गैरीसन के आसपास अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। यह स्थान एक महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है जो तेहरान से ईरानी समर्थित बलों को दक्षिणी लेबनान तक और इज़राइल के दरवाज़े तक जोड़ सकती है। इराक और सीरिया दोनों में,अमेरिकी सैनिक उस रास्ते को बाधित करते हैं जो ईरान के लिए पूर्वी भूमध्य सागर तक एक निर्विवाद भूमि पुल हो सकता था।

ईरान से आने जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों और महत्वपूर्ण घटनाओं पर सीआईए की पैनी निगाहें होती है। ईरान पर जमीन,आसमान और समुद्र से नजर रखने में अमेरिकी सैन्य अड्डे मददगार बने हुए है। 2020 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख वैज्ञानिक फ़ख़रीज़ादेह की ईरान की राजधानी तेहरान के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। ईरान में जहां फ़ख़रीज़ादेह की हत्या की गई है,वहां से परमाणु और मिलिट्री साइट्स पास ही हैं। फ़ख़रीज़ादेह बेहद कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते थे। फ़ख़रीज़ादेह कि हत्या बेहद गोपनीय मिशन के तहत सुनियोजित रणनीति से की गई और ऐसे सनसनीखेज काम करने के लिए मोसाद कुख्यात रही है। 2020 में ही बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमलें में ईरान के टॉप मिलिटरी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। सुलेमानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे जो दुनिया भर में ईरान विरोधी ताकतों को निशाना बनाती रही है।

सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा था,वे 1998 से ईरान की कुद्स फ़ोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। अब हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को तेहरान में निशाना बना कर मोसाद और सीआईए ने ईरान को तो सकते में डाल ही दिया है। इसके साथ ही चीन की फिलिस्तीन चरम पंथी समूहों में एकता कायम करने की कोशिशें भी धराशाई हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह विश्वास किया जाता है की किसी दूसरे देश में सैन्य आधारित नीतियों से गहरी राजनीतिक समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन इसराएल और अमेरिका के लिए स्थापित मान्यताएं कभी बाधा नहीं समझी जाती और वह अपने राजनीतिक और सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी कदम उठाने से परहेज नहीं करते है।

हानिया की मौत के ठीक पहले ईरानी संसद में नये राष्ट्रपति की शपथ के दौरान अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएं गए थे। वहीं तेहरान में नये राष्ट्रपति का शपथ समारोह को मोसाद और सीआईए ने बढिया मौका बना दिया तथा हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या कर गजा संघर्ष को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस काम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक —संजय सक्सेना,
प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 म.प्र.। ई-मेल : dspbpl67@gmail.com, वेबसाईट: dainiksandhyaprakash.in

फ़रहत सराय कमेटी के नए पदाधिकारियों का किया स्वागत, अध्यक्ष ने जताया आभार

नर्मदा पुरम/ हरदा फ़रहत सराय कमेटी की नई कमेटी बनने के उपरांत अध्यक्ष यासीन खान और सचिव मुस्ताक खान का समाज के सभी लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें कोषाध्यक्ष जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, सहा सचिव जनाब मोहम्मद ज़ाहिद, और सदस्य जनाब दीपील शामिल हुए।

बसपा नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड में एक और गिरफ्तार

छतरपुर। बसपा नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड में एक और आरोपी शिवेंद्र सिंह को सिविल लाईन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुरानी दुश्मनी के चलते हुई इस हत्या में शामिल मुख्य आरोपी रानू राजा व उसके परिजनों, 2 शूटर एवं शूटर का मीडिएटर सहित एक दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सागर रोड स्थित गजराज पैलेस के सामने 4 मार्च को हमलावरो ने बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सिविल लाईन थाना में अपराध क्रमांक 123/24 पर आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण सीसीटीवी फुटेज एवं साक्ष्यों के आधार पर हत्या में शामिल आरोपी आकाश सक्सेना, एक महिला आरोपी, मुख्य आरोपी रानू राजा सहित पिता प्रतिपाल सिंह व परिजन तथा मथुरा से 2- 2 लाख रुपए में हायर किए गए दो शूटर एवं शूटर से डीलिंग करवाने वाले मीडिएटर विकास पचौरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी के चाचा गोविंद सिंह, चचेरे भाई शानू राजा, हत्या की घटना में संबंधित आरोपी राजपाल सिंह चौहान संजय नगर थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

राजस्व महाभियान 2.0 में दबाव और संसाधनों की कमी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। राजस्व अधिकारियों ने राजस्व महाभियान 2.0 के तहत अत्यधिक दबाव और संसाधनों की कमी के चलते मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री और सचिव राजस्व विभाग के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कि तकनीकी स्टाफ और पर्याप्त संसाधनों की कमी से प्रक्रिय में समय लगता है। गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। राजस्व अधिकारियों का कहना है अन्य विभागीय कार्यों के साथ कानून व्यवस्था, प्रोटोकॉल और अन्य विविध कार्यों में भी उन्हें शामिल होने से भी कार्यभार बढ़ जाता है। बताया कि स्ख्रष्ट के प्रावधानों का पालन न करने पर अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिससे उनमें मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कहा कि पूर्व राजस्व अभियानों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बंटान की कार्यवाही नियमानुसार न होने से कई तहसीलदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अविवादित नामांतरण और बंटवारे हेतु ई-पंजी की व्यवस्था ञ्चस्ह्रस्स् में दी जाए। विवादित मामलों का समाधान सिविल न्यायालय से कराया जाए।

खर्च श्रम विभाग का संचालन शिक्षा विभाग करता है

श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्य ने किया 4 करोड़ का घोटाला, कार्रवाई के बजाय आरोपी को बना दिया भोपाल श्रमोदय विद्यालय का प्राचार्य

संभागायुक्त की जांच और सिफारिश रद्दी की टोकरी में.. विभाग प्रमुख का खास है आरोपी.. आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में भी मामला, लेकिन जांच प्रभावित की जा रही

भोपाल। प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगाने वाले अधिकारी किस तरह न केवल बच रहे हैं अपितु उन्हें बेहतर प्रभार दिया जा रहा है, ये स्कूल शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। एक अधिकारी की जांच के बाद करोड़ों रुपए के आरोपी की वसूली और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई करनेकी सिफारिश संभागीय कमिश्नर करते हैं पर इसके बावजूद संबंधित विभाग के आयुक्त इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। चार करोड रुपए की वसूली जिस अधिकारी से करने के दिशा निर्देश दिए इस अधिकारी को दूसरे स्कूल का प्राचार्य बनाकर भ्रष्टाचार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया यह मामला श्रम विभाग और मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मालूम यह भी चला है कि विभाग प्रमुख के प्रमुख हैं आरोपी प्राचार्य और इसीलिए उन पर आज तक कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर में स्थित श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्य विजय सिंह महोबिया पर जबलपुर में संस्था की एक 40 करोड रुपए के भवन निर्माण में बड़े घोटाले करने लगे हैं। सूत्रों की माने तो इस 40 करोड रुपए की लागत से बनने साले भवन का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ बिना निर्माण कार्य पूरे हुए ही प्राचार्य विजय सिंह ने कान्ट्रैक्टर से भवन का अधिग्रहण कर लिया और संबंधित ठेकेदार को उसके कार्य का भुगतान कर दिया जबकि भवन का निर्माण कार्य 10 से 15 परसेंट शेष रह गया था जिसकी लागत 4 करोड़से 6 करोड रुपए हो सकती है। इस बात की जानकारी जब लोगों को लगी तो इस मामले की शिकायत जबलपुर संभाग के आयुक्त से की गई सम्भागीय आयुक्त ने मामले की जांच कर इस मामले में प्राचार्य विजय सिंह की दोषी पाया और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर प्राचार्य विजय सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और 4 करोड रुपए की उनसे वसूली से करने के निर्देश का पत्र विधिवत कमिश्नर शिक्षा विभाग को लिखा आश्चर्य की बात ती यह है कि कमिश्नर शिक्षा विभाग ने इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और जबलपुर श्रमोदय विद्यालय से विजय सिंह को हटाकर भोपाल के श्रमोदय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ कर दिया।

जबलपुर संभागायुक्त ने जांच के बाद प्राचार्य महोबिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए 6 अक्टूबर 2023 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा था। 5 माह का समय बीत चुका है अब तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होना तो छोड़िए उन्हें प्राचार्य के पद से भी नहीं हटाया गया है। महोबिया वर्तमान में भोपाल के मुगालिया छाप नीलबड़ स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में बतौर प्राचार्य सेवाएं दे रहे हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए आयुक्त से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस पर किसी भी तरह का जवाब देना ठीक नहीं समझा। अब श्रम विभाग और शिक्षा विभाग में यह चर्चाएं जोरो पर चल रही है कि जिस अधिकारी से 4 करोड़ रुपए वसूली के निर्देश और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए पात्र जबलपुर संभाग आयुक्त ने लिखा उसके खिलाफ कार्रवाई करना, वसूली करना तो दूर शिक्षा विभाग के आयुक्त ने उसकी पदस्थापना जबलपुर से हटकर भोपाल के श्रमोदय विद्यालय में करके फिर भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देने के लिए कर दी सहने अब दोनों विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में यह चर्चा है कि इस अधिकारी को सजा मिली है या उसे प्रोत्साहित किया गया है।

चार करोड़ का काम हुआ ही नहीं

जबलपुर संभागायुक्त ने अपने पत्र में यह भी बताया था कि कुल 40 करोड़ के निर्माण कार्य में 10त्न कार्य जो कि करीब 4 करोड़ का था, मौके पर हुआ ही नहीं है। यहीं वजह रही कि श्रमोदय विद्यालय जबलपुर के तत्कालीन प्राचार्य विजय सिंह महोबिया पर निर्माण निर्माण एजेंसी को 4 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिलाने का आरोप सही साबित हो गया। इसी को देखते हुए संभागायुक्त ने महोबिया से ही उक्त राशि की वसूली करने के साथ ही उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा था।

स्कूल श्रम विभाग का, संचालन शिक्षा विभाग करता है

प्रदेश में जो भी श्रमोदय विद्यालय हैं, उनका संचालन शिक्षा विभाग ही करता है, जबकि उनका पूरा खर्च श्रम विभाग चलाता है। इन विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चे शिक्षा पाते हैं। अब यह मामला प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की जानकारी में भी लाया जा रहा है।

कांग्रेस एमएएल पर आदिवासी महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का आरोप, प्रकरण दर्ज

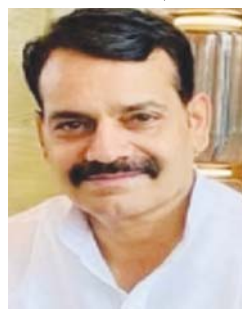

ग्वालियर कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर ग्रामीण के विधायक पर आदिवासी महिलाओं ने मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिलाओं ने कहा कि विधायक ने उन्हें बाल पकड़कर पीटा और गालियां दी। महिलाओं ने इस मामले में सोमवार को एसपी धर्मवीर सिंह भदौरिया से शिकायत की थी। जबकि, साहब सिंह गुर्जर ने इन सभी आरोपों को गलत बताया।

महाराजपुरा के मऊ पहाड़ी की रहने वाली महिलाएं सोमवार दोपहर एसपी ऑफिस पहुंची थीं। महिलाओं ने शिकायत में कहा कि वे बिजली की समस्या को लेकर कई बार विधायक के पास गए। उनके गांव में ढाई सौ से ज्यादा घर हैं। कई बार ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। वे लोग सुबह इसी सिलसिले में साहब सिंह गुर्जर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन विधायक ने बिना बात सुने ही अभद्रता से बात की और गाली दी।

उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब हम लोग घर के बाहर खड़े होकर चर्चा कर रहे थे, तभी वहां विधायक आ गए और उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है? इतना कहकर मुन्नी देवी को बाल पकड़कर पटक दिया। इस दौरान बच्ची बाई ने बचाने की कोशिश की, तो उसको भी पीट दिया। अन्य महिला रामकली ने बताया कि मेरे और बेटे के साथ भी मारपीट की गई। जब थाने जाने की बात कही तो विधायक ने बोले कि क्या करेंगे एसपी, आईजी? मैं ही ?एसपी और आईजी हूं।

विधायक ने सारी बातों को झुठलाया

इस बारे में साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि कुछ महिलाएं आई थीं। उनकी समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं आज ही ट्रांसफार्मर लगाने की बात कहते हुए चिल्लाने लगीं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी बात की। महिलाएं हंगामा कर रही थीं। बाद में पीएसओ योगेन्द्र से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। उन्हें समझाकर रवाना कर दिया। महिलाएं थीं इसलिए हमारी ओर से शिकायत नहीं कराई गई। बाद में इनके एसपी ऑफिस पहुंचने की जानकारी मिली, तब पीएसओ को थाने भेजा और लिखित शिकायत की गई।

हाई कोर्ट के मुख्य सचिव को निर्देश, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा पर कार्रवाई की जाए

भोपाल। हाजिरी माफी पर हाई कोर्ट को सीधे पत्र लिखना नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा पर भारी पड़ गया। कलेक्टर के रवैये पर आपत्ति लेते हुए कहा कि उनका रवैया न?यायालय की गरिमा के हनन के समान है। लिहाजा, मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह इस कृत्य के लिए कलेक्टर नर्मदापुरम के विरुद्ध कार्रवाई करें। यहां तक कि कलेक्टर का पत्र लेकर जबलपुर जाकर जज को सौंपने वाले अपर कलेक्टर और तहसीलदार को भी उनकी इस कार्यवाही की सजा मिल गई। यह मामला नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान का है।

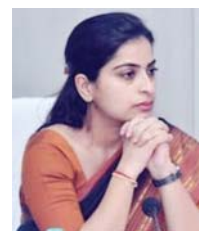

हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा के उस रवैये को गंभीरता से लिया, जिसके तहत उन्होंने हाजिरी माफी के लिए सीधे जज को पत्र लिख दिया। न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्टर नर्मदापुरम का सीधे कोर्ट को पत्र लिखना सही नहीं था। उनका यह रवैया कोर्ट की गरिमा के हनन जैसा है। कायदे से कलेक्टर को महाधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष रखना चाहिए था। अतः मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे इस कृत्य के लिए कलेक्टर नर्मदापुरम के विरुद्ध कार्रवाई करें और अपनी कार्रवाई के संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश करें।

हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने अपने 30 पेज के फाइनल ऑर्डर में कहा कि इस पूरे मामले को हमने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव (सीएस) वीणा राणा को निर्देश देते हुए कहा कि एक महीने के अंदर कलेक्टर नर्मदापुरम के खिलाफ एक्शन लीजिए, हाईकोर्ट के जज को डायरेक्ट नाम से चिट्ठी लिखकर भेज दी। कोर्ट ने सीएस से 30 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार को काम का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अपर कलेक्टर और तहसीलदार से एक साल के लिए मजिस्ट्रेट पावर भी छीन लिए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार अगर चाहे तो अपर कलेक्टर, तहसीलदार और कलेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल और करप्शन का केस भी दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट जस्टिस ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीणा को हाजिर होने को कहा था। लेकिन, कलेक्टर ने खुद कोर्ट जाने की जगह अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी थी। इसी मामले पर कलेक्टर पर कार्यवाही का पत्र लिखा गया है।

कृष्ण मृग का शिकार कर ले जा रहे आरोपी पर थाना रनेह पुलिस की कार्यवाही

दमोह श्रुतकीर्ति सोमवंशी पुलिस अधीक्षक जिला दमोह, संदीप मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी हटा नितेश पटेल के निर्देशन में जिले में जानवरों की तस्करी रोकने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। जिसके के तहत थाना प्रभारी रनेह उप निरीक्षक चंदन सिंह थाना रनेह अंतर्गत मृग का शिकार करने वाले आरोपी को गिरफ्त में लेकर कार्यवाही की गई है।

यह है घटनाक्रमःदिनांक 30/07/24 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक शिकारी द्वारा मृग (हिरण) का शिकार कर मोटर साईकिल से ग्राम सड़क हरदुआ की ओर जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी रनेह एवं थाना स्टाफ ने मौके पर पहुंच कर स्नेह-हटा रोड पर शिकारी के कब्जे से एक मृत मृग को दस्तयाब किया। जिसमें आरोपियों द्वारा खेत में घूम रहे हिरण को बंदूक से शिकार करना स्वीकार किया। मौके की कार्यवाही एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषि तिवारी द्वारा पहचान कार्यवाही कराये जाने उपरांत उक्त मृत कृष्ण मृग की पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराये जाने हेतु पशु चिकित्सालय हटा भेजा गया। मौके से गिरफ्तार 01 आरोपी से पूछताछ की गई एवं प्रकरण में फरार 01 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।

शासकीय विद्यालय मुड़िया में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

दमोह म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धर्मेश भट्ट के मार्गदर्शन में शासकीय विद्यालय मुड़िया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तृतीय जिला न्यायाधीश महिमा कछवाहा, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, प्राचार्य शोभा दीवान एवं समस्त स्टाफ सहित छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे। इस अवसर पर तृतीय जिला न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने बच्चों को मोटरयान अधिनियम के तहत जानकारी देते हुये बताया वर्तमान में दुर्घटना से मृत्यु दर बढ़ गई हैं, लोगों द्वारा लापरवाही व यातायात के नियमों को अनदेखा किया जाकर तेज वाहन चलाये जाते है और दुर्घटनाएं होती है, जिससे कई परिवार अपने परिजनों को खोकर नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने सभी से यातायात के नियमों का पालन करते हुये वाहन चलाने के लिये कहा। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को साईबर क्राईम, शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो अधिनियम एवं बाल विवाह के संबंध में जानकारी दी।

जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनो मौत

बच्चे का शव झोले में लेकर दो दिन घूमते रहे परिजन

सांध्य प्रकाश बैतूल। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक प्रसूता सुमित्रा बाई को प्रसव के लिए जिला अस्पताल रैफर किया था। मृतिका सुमित्रा की मां सुशीला बाई के मुताबिक जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने सुमित्रा के हाथ बांधकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की प्रसव के बाद बच्चा मृत पैदा हुआ। जिसका शव एक थैले में रखकर परिजनों को सौंप दिया गया। इसके ठीक अगले दिन की शाम सुमित्रा बाई को नर्सिंग स्टाफ ने कुछ दवाइयां दी जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी भी मौत हो गई।सुमित्रा के पति अर्जुन का कहना है। कि पत्नी से पहले बच्चा मृत अवस्था मे जन्मा था। जिसके शव को नर्सिंग स्टाफ ने एक थैले में रखकर परिजनों को सौंप दिया। शहर में बच्चे का अंतिम संस्कार कहां और कैसे करें। इसी सोच में पड़े परिजन दो दिन से बच्चे का शव लेकर घूम रहे है। इस घटना से ठीक 48 घण्टे पहले भी जिला अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद उसके परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर ग़लत इलाज करने और लापरवाही का आरोप लगाया था। प्रशासन ने जांच शुरू की है। ये लगातार दूसरा मामला है। जब एक प्रसूता की मौत को लेकर हंगामा हो रहा है।

इस बार भी एक जांच दल गठित किया गया है। लेकिन ऐसे मामलों में जांच दल तो गठित किये जाते है। लेकिन जांच रिपोर्ट का खुलासा कभी नहीं किया जाता। वहीं जिला अस्पताल में सारी आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद प्रसूताओं की मौत के मामले बढ़ते जा रहे है। जो एक चिंता का विषय है। परिजनों ने मृत शिशु का शव झोले में रखकर प्रदर्शन किया है। और पोस्पार्टम नही किए जाने की मांग करी है। और पूरे मामले की वीडियो फुटेज रिकार्डिंग भी मांगी है।

इनका कहना है।

सुमित्रा बाई को डिलेवरी के लिए भर्ती किया गया था। जंहा दोनो की मृत्य हो गई चुकी है। लापरवाही को लेकर ज्ञापन दिया है। जिस पर जांच करवाई जाएगी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्तिथि साफ हो पाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

डिप्टी कलेक्टर, मकसूद खान

बाघ दिवस के अवसर पर हुए कई कार्यक्रम

सुल्तानपुर //अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर वन मंडल रायसेन द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के साथ जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किया। आज सुबह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से वन परिसर सागर तिराहे तक बाघ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिसमें कन्या शिक्षा परिषर की छात्राओं ने वन स्टॉप के साथ शिरकत की इस रैली का नेतृत्व वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम रायसेन बृजेंद्र तिवारी द्वारा किया गया साथ में पूर्व रायसेन एवं पश्चिम रायसेन का वन अमला मौजूद रहा। वनमंडल रायसेन की ओर से शासकीय विद्यालय बनखेड़ी के छात्रों के द्वारा बाघ जागरूकता कार्यक्रम के तहत %मैं भी बाघ% थीम पर ग्राम सुरई एवं ग्राम नीमखेड़ा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया तत्पश्चात वन परिसर में माननीय विधायक डा प्रभुराम चौधरी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, जिला कलेक्टर महोदय श्री अरविंद दुबे, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास शाहवल, वन मंडल अधिकारी महोदय श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजू पवन भदोरिया, उपवन मंडल अधिकारी रायसेन सुधीर पटले, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व रायसेन प्रवेश पाटीदार, वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम रायसेन बृजेंद्र तिवारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी रोहित पटेल समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा ड्राइंग बनाकर वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश दिया एवं गणमान्य अतिथियों के सामने नुक्कड़ नाटक कर बाघ संरक्षण का संदेश दिया। माननीय अतिथियों द्वारा विजेता विद्यार्थियों को तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम रायसेन बृजेंद्र तिवारी समेत बाघ रेस्क्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 20 वन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

3 हजार में तय होता है हॉस्टल में एडमीशन, अधीक्षका पर आरोप... कमिश्नर सहित पुलिस में भी की शिकायत

शहडोल। प्रदेश सरकार भले ही आदिवासी बाहुल्य ईलाकों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था को लेकर संवेदनशील हो और इस पर लाखों करोड़ों खर्च किये जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। हालात ऐसे हैं कि आदिवासी बाहुल्य ईलाका आज भी कई मामलों में शोषित नजर आता है, और ऐसी तमाम शिकायते सामनें आ जाती है तो इस बात को पुष्ट करती नजर आती है। कुछ ऐसा ही मामला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सोहागपुर से सामनें आया है जहां 9 वीं कक्षा में पढ़नें वाली एक छात्रा के अभिभावकों द्वारा छात्रावास में प्रवेश दिये जानें के नाम पर वहां तैनात अधीक्षिका श्रीमती सुधा पटेल पर 3 हजार रुपये लेकर प्रवेश दिये जानें के गंभीर आरोप लगाये हैं। पीडित अभिभावकों नें मामले की शिकायत जनसुनवाई में करते हुये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी कर न्याय की गुहार लगाई है।

दाखिले के लिये पूर्व में ही कटा ली थी रशीद

पीडित अभिभावकों नें विद्यालय की रशीद दिखाते हुये बताया कि उनके द्वारा जून माह में ही दाखिले का शुल्क जमा करा दिया गया था। उन्होनें बताया कि वह जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और अपनी बच्ची को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं। शासन स्तर पर जहां तमाम योजनाएं संचालित हैं वहीं इन योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार है। जिम्मेदार अमला किसी भी हाल में मोटी कमाई करना चाहता हैं। पीडित नें बताया कि यदि वह इतनें ही सक्षम होते तो कहीं और अपनी बिटिया को पढ़ा लेते। अभिभावकों नें कहा कि वह 2 हजार रुपये का किसी तरह इंतजाम करके देनें तो तैयार भी थे लेकिन अधीक्षिका नहीं मानी जिससे व्यथित होकर और अपने बच्ची की भविष्य कि चिंता में उन्हें शिकायत कर न्याय की गुहार लगानें पर मजबूर होना पड़ा है।

मनमर्जी की तर्ज पर तैनात है अधीक्षक

एक तरफ जहां शासन स्तर पर अधीक्षकों कि नियुक्ति और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर तमाम नियम और मापदण्ड निर्धारित है वहीं जमीनी स्तर पर इनकी खुलकर धज्जियां उडाई जा रही है। जिले के छात्रावासों में अंगद के पैर की तरह जगह बनाये बैठे ऐसे तमाम अधीक्षक हैं जो अपनें मूल कार्यो से कोसो दूर है। छात्रावासों में लाखों रुपये के फंड और उसके व्यय की जानकारी को यदि बारीकी से जिम्मेदार खंगाले तो तमाम चौकानें वाले खुलासे सामनें आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक शासकीय राशि के दुरुपयोग और कमीशन के फेर के ऐसे तमाम पहलू हैं जिनमें जांच की आवश्यकता हैं लेकिन मैनेजमेंट के दम पर चलनें वाले इस खेल में सबकी भागीदारी कुछ इस तरह फिक्स है कि कोई इस दिशा में कार्यवाही नहीं करना चाहता। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया बेटियों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील हैं वहीं आदिवासी बाहुल्य इलाके से इस तरह की शिकायते सिस्टम के पारदर्शी रवैये पर सवाल खड़ी करती नजर आती है।

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

इधर कमिश्नर कार्यालय के सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश ने शहडोल संभाग के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी तथा निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान शहडोल जिले के ग्राम पंचायत श्यामडीह निवासी मदन सिंह ने आवेदन देकर बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोहागपुर की अधीक्षिका सुधा पटेल के पास मैंने पूर्व में छात्रावास का प्रवेश फार्म भरकर दे दिया था। उन्हीं के आश्वासन पर मैंने अपनी बच्ची कु0अंशिका सिंह को शासकीय कन्या उ.मा. विद्या. सोहागपुर जिला शहडोल में प्रवेश दिलाया था। छात्रावास से सम्बद्ध विद्यालय में प्रवेश दिलाने के पश्चात भी छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती सुधा पटेल द्वारा बिना तीन हजार रूपये लिये प्रवेश देने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहना था कि मेरे बच्ची को छात्रावास प्रवेश दिलाया जाएं। जिस पर संयुक्त आयुक्त विकास ने संबंधित विभाग के अधिकारी की ओर आवेदन प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहडोल जिले ग्राम गोडिनबूडा पोस्ट रेउसा निवासी भगवानिया सिंह एवं मायावती पांच ने आवेदन देकर बताया कि हम दोनों विगत कई वर्षों से प्राथमिक पाठशाला गोडिनबूडा मे एमडीएम कार्यक्रम में सहायिका के पद पर कार्य करते आ रहे है। लेकिन वर्ष 2023 से अब तक का पारिश्रमिक का भुगतान नही किया गया है। उनका कहना था कि हमें सहायिका पद का मानदेय प्रदान किया जाए। जिस पर संयुक्त आयुक्त विकास ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल की ओर आवेदन प्रेषित कर मानदेय भुगतान करने के निर्देष दिए। इसी प्रकार जनसुनवाई में शहडोल संभाग के दूर-दराज से आए अन्य लोंगो की भी सुनवाई की गई तथा निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई में उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनिषा पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थें।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सहित दो वारंटी भेजे जेल

छतरपुर। ईशानगर थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सहित दो वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना ईशानगर पुलिस ने वर्ष 2023 के नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के प्रकरण के फरार आरोपी महेंद्र पटेल ग्राम पनौठा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वर्ष 2019 के भरण पोषण संबंधित प्रकरण के फरार वारंटी सुमित अहिरवार ग्राम अजोखर थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था।

भोपाल विकास प्राधिकरण

क्र. 2006/राजस्व/भोविप्रा./2024 दिनांक 30.07.2024

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की शिवानी कॉम्पलेक्स शिवाजी नगर योजना में स्थित प्रकोष्ठ क्रमांक 2/1, श्री वी.आर. सप्रे आ. श्री एम.के. सप्रे के नाम पर अंकित है, आवंटी श्री वी.आर. सप्रे द्वारा प्राधिकरण की बिना अनुमति के उक्त प्रकोष्ठ श्री ज्योति प्रकाश खरे आ. श्री किशोर शरण खरे एवं श्रीमती ज्योति खरे पत्नी श्री ज्योति प्रकाश खरे को दिनांक 28.04.2009 को पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत करा दिया गया, श्री ज्योति प्रकाश खरे आ. श्री किशोर शरण खरे द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपने नाम पर नामांतरण करने की मांग की गई है।

यदि उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी

सोशल मीडिया से

WHISPERSINTHECORRIDORS.COM

(WE BROKE THIS NEWS IN INDIAN MEDIA FIRST IN MORNING OF JULY 30, 2024

Mrs Preeti Sudan appointed as Chairperson, UPSC

Mrs Preeti Sudan, Member UPSC, has been appointed as Chairperson, Union Public Service Commission. Mrs Sudan, who belongs to a 1983 batch IAS officer of AP cadre, served as Union Health Secretary during the period of COVID-19 pandemic.

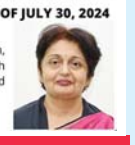

आज का पंचांग

दिनांक - 31 जुलाई 2024
दिन - बुधवार
शक संवत - 1946
विक्रम संवत - 2081
दिशाशूल - उत्तर
मास - श्रावण
पक्ष - कृष्ण पक्ष
शुभ प्रभात
आपका दिन शुभ हो।
तिथि - एकादशी - 03:55 PM तक फिर द्वादशी
नक्षत्र - रोहिणी - 10:12 AM तक फिर मृगशिरा
अभिजित मुहूर्त - कोई नहीं
राहु काल - 12:27 PM से 02:09 PM
यमघण्ट - 08:24 AM से 09:18 AM तक
आज का व्रत - रोहिणी व्रत, कामिका एकादशी

सिर्फ एक बार जमा करें पैसा, फिर हर महीने मिलेगी पेंशन, एलआईसी की धांसू स्कीम

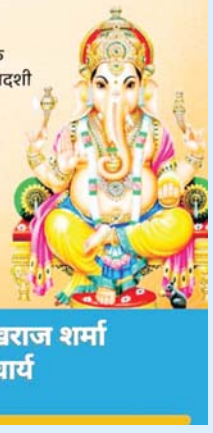

इंदौर। हर शख्स अपनी कमाई से बचत करते हुए ऐसी जगह निवेश करता है, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। साथ ही नियमित इनकम होती रहे। इस परेशानी को हल करने के लिए एलआईसी द्वारा कई बीमा प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जो पेंशन की निश्चित गारंटी देते हैं।

इनमें से एक एलआईसी न्यू जीवन शांति पॉलिसी है। इस स्कीम में एक बार निवेश करने पर पेंशन जीवनभर के लिए तय हो जाती है। एलआईसी के पास हर आयु के व्यक्ति के लिए प्लान हैं। न्यू जीवन शांति सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें हर साल एक लाख रुपये की पेंशन पा सकते हैं।

एलआईसी न्यू जीवन शांति पॉलिसी के लिए 30 से 79 साल तक ऐज लिमिट है। इस प्लान को खरीदने के दो विकल्प हैं, जिनमें पहला डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ और दूसरा डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ है। यानी इस ग्राहक सिंगल या संयुक्त प्लान चुन सकता है। एलआईसी की इस स्कीम में निवेश करने पर ब्याज भी मिलता है।

पॉलिसी में डेथ कवर शामिल

न्यू जीवन शांति स्कीम में पेंशन के साथ डेथ कवर का लाभ भी मिलता है। अगर पॉलिसीधारक का निधन हो जाता है तो उसके अकाउंट में जमा रकम नॉमिनी दी जाती है। इस प्लान को सरेंडर भी कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम एक बार में 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं, जबकि अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है।

हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन?

एलआईसी न्यू जीवन शांति स्कीम के सेल्स ब्रोशर के मुताबिक, सिंगल लाइफ के लिए 10 लाख रुपये की पॉलिसी खरीदने पर 11,192 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ के मामले में मासिक पेंशन 10,576 रुपये हो सकती है।

इवेक्सिया लाइफकेयर लिमिटेड बोर्ड ने एफसीसीबी के कन्वर्जन को मंजूरी दी

मुंबई, एजेंसी। इवेक्सिया लाइफकेयर लिमिटेड (बीएसई- 524444), जो केमिकल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स के अन्य विभिन्न उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है, ने घोषणा की है कि कंपनी के सदस्यों ने 9 जुलाई, 2022 को एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित करके फॉरेन करंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जारी करने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने एफसीसीबी के इश्यू की टर्म और कंडीशंस के अनुसार 25 बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में बदलने पर विचार किया और मंजूरी दे दी। हाल ही में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 17 जून, 2024 को हुई अपनी मीटिंग में एफसीसीबी के इश्यू की टर्म और कंडीशंस के अनुसार 75 बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में बदलने पर भी विचार किया और मंजूरी दी।इससे पहले, इवेक्सिया लाइफकेयर लिमिटेड ने घोषणा की थी कि उसने इवेक्सिया लाइफकेयर अफ्रीका लिमिटेड (ष्टद्धह- 14497377) नाम से एक सहायक कंपनी बनाई है, जो इंग्लैंड और वेल्स के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है। इंग्लैंड और वेल्स के लिए कंपनी रजिस्ट्रार ने इसके लिए एक इश्यू सर्टिफिकेट जारी किया है। एवेक्सिया लाइफकेयर ने अफ्रीका में पैथोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए नई सहायक कंपनी इवेक्सिया लाइफकेयर लिमिटेड (बीएसई- 524444) का गठन किया, जो फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स के विभिन्न अन्य उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है।

लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड बोर्ड ने इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट को मंजूरी दी

मुंबई एजेंसी। रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड (बीएसई- 540952, एनएसई- रुरु) ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने 1,48,340 वारंट्स को 1 रुपये प्रति फेस वैल्यू के 14,83,400 इक्विटी शेयर्स में बदलने की मंजूरी दे दी है। 5 अक्टूबर, 2023 को प्रेफेरेंशिएल बेसिस पर आवंटित 10,38,371 वारंट्स में से 2.25 करोड़ रुपये का जमा अमाउंट ऑर्चर्ड रोड प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ।

हाल ही में कंपनी ने 2,47,230 वारंट्स को 1 रुपये प्रति फेस वैल्यू के 2,47,23,00 इक्विटी शेयर्स में बदलने की मंजूरी दे दी है। 5 अक्टूबर, 2023 को प्रेफेरेंशिएल बेसिस पर आवंटित 10,38,37,10 वारंट्स में से 3,74,99,846.4 रुपये कुल राशि मिलने पर कीवी डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड से (प्रति वारंट इश्यू प्राइस का 75 प्रतिशत) प्राप्त हुए।

इससे पहले, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी आय की घोषणा की। ऑपरेशनल रेवेन्यू 54.76 करोड़ रुपये और एबिटा 10 करोड़ रुपये सालाना 29 प्रतिशत की वृद्धि पर आया। शुद्ध लाभ दोगुने से भी अधिक हो गया, 2.52 करोड़ रुपये (फाइनेंशियल ईयर 23) से बढ़कर 5.30 करोड़ रुपये (फाइनेंशियल ईयर 24) हुआ।

श्रेष्ठ फिनवेस्ट लिमिटेड बोर्ड 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट पर गौर करेगा

मुंबई, एजेंसी। फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में अग्रणी श्रेष्ठ फिनवेस्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड 31 जुलाई, 2024 को कंपनी के इक्विटी शेयर्स का 1-2 अनुपात में सब-डिवीज़न अर्थात, 2 रुपये की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर्स के सब-डिवीज़न पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। हाल ही में, कंपनी ने घोषणा की कि श्रेष्ठ फिनवेस्ट लिमिटेड और फेलिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बीच मौजूदा बिज़नेस अरेंजमेंट को जारी रखते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी इनीशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक फैसिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके एक बार फिर हाथ मिलाया है, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य से रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन वॉटर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में ऋण देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

इस नए एग्रीमेंट की मदद से, फेलिक्स रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन वॉटर और वॉटर रीसाइक्लिंग से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए फेलिक्स द्वारा आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ खरीदे गए ऑर्डर हेतु प्लांट इंस्टॉलेशन के कैपिटल वर्क के लिए कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन रुपये की दो चरणों में फंडिंग की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी और वॉटर सेग्मेंट में विविधता को मज़बूत फाइनेंशियल सपोर्ट देने, स्थिरता को बढ़ावा देने और ग्रीन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था फेलिक्स के फाइनेंशियल सपोर्ट को मज़बूत करेगी।

आशापुरा लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 3 खुला

मुंबई, एजेंसी। आशापुरा लॉजिस्टिक्स भारत में एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी है। जो मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग और माल अग्रेषण खंड, परिवहन (प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स सहित), वेयरहाउसिंग और वितरण और अन्य सेवाओं (तटीय आंदोलन सहित) में संचालित होता है। कंपनी पूरे भारत में काम करती है। वे 9 शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से इक्विटी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और 30 जुलाई 2024 को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश खोलने की घोषणा की है।स्थापना के बाद से 20 से अधिक वर्षों के परिचालन अनुभव के साथ कंपनी अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति एकीकृत सेवा पेशकश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और वाहन बेड़े के विशाल नेटवर्क के साथ विभेदित लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है। यह एक परिसंपत्ति-आधारित व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है जिसमें अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए आवश्यक संपत्ति जैसे वाणिज्यिक वाहन, कंटेनर और गोदाम, या तो स्वामित्व में हैं या पट्टे के आधार पर व्यापार भागीदारों के नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती हैं। तदनुसार, कंपनी ने अपने वाहनों के बेड़े के साथ-साथ व्यावसायिक साझेदारों का एक नेटवर्क भी बनाए रखा है, जिनसे वह आवश्यकतानुसार आवश्यक वाहन किराये पर लेती है। इसके अतिरिक्त इसकी सामग्री सहायक कंपनी जय अंबे ट्रांसमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड भी परिवहन सेवा व्यवसाय में शामिल है।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में 76 आवेदनों पर की सुनवाई

छतरपुर। कलेक्टर संदीप जी.आर. की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई सम्पन्न हुई। इस दौरान एडीएम मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर काजोल सिंह, एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कलेक्टर के निर्देशन में निःशुल्क शिकायती आवेदन लिखवाने की व्यवस्था कि गई है। आवेदककर्ता को आवेदन में मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। कलेक्टर श्री जी.आर. ने जनसुनवाई में प्राप्त 76 शिकायती आवेदनों की सुनवाई करते हुए परीक्षण के आधार पर संबंधित विभाग को आवेदन निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही दिव्यांगों के शिकायती आवेदनों की सुनवाई अलग से की गई। जनसुनवाई में शिक्षा, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास, विद्युत मण्डल, स्वास्थ्य, खाद्य, आदिम जाति, श्रम, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न शिकायती आवेदन प्राप्त हुए।

फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि आज

छतरपुर। खरीफ मौसम 2024 में छतरपुर जिले के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की छति पूर्ति भरपाई के लिए आज 31 जुलाई 2024 तक फसल बीमा करा सकते हैं। उप संचालक कृषि डॉ. के. के. वैद्य ने बताया कि जिले स्तर पर उड़द, मूंग फसल, जिसका पूरे जिले के समस्त किसान फसल बीमा करा सकते है। तहसील स्तर पर ज्वार तिल एवं मूंगफली है। ज्वार फसल गौरिहार और चंदला तहसील में, तिल फसल घुवारा तहसील को छोड़कर सभी तहसीलों में तथा मूंगफली फसल बक्सवाहा तहसील को छोड़कर, जिले की समस्त तहसीलों में अधिसूचित है तथा पटवारी हल्का स्तर पर जो जिले के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का है उनमें धान असिंचित, सोयाबीन, एवं अरहर फसल को शामिल किया गया है। खरीफ फसल में जिले में लागू ऋण मान सीमा प्रति हैक्टेयर लागत का किसानों को फसल बीमा कराने के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि फसल बीमा कंपनी को देय होगी। अऋणी किसान 2 प्रतिशत राशि जमा कर किसी भी निजी सायवर सेन्टर, सीएससी सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, स्वयं अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई के पूर्व करा सकते है।

बल्ककॉर्प इंटरनेशनल का आईपीओ खुला

मुंबई, एजेंसी। 2009 में स्थापित बल्ककॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड एक ढ्डस्ह 9001-2015, ढ्डस्ह 14001-2015, ढ्डस्ह 45001-2018 और क्चक्रष्ट प्रमाणित कंपनी है, जो फूड ग्रेड फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। कंपनी की विनिर्माण इकाई चांगोदर, अहमदाबाद में स्थित है। कंपनी अनुकूलित पैकेजिंग समाधान स्नढ्ढक्चष्ट बैग (जंबो बैग) की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। कंपनी बीआरसी द्वारा निर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करके संयंत्र परिसर में उच्च सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करती है। बल्ककॉर्प इंटरनेशनल रु. 10 प्रत्येक 19,78,800 अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर प्रदान करता है।

कंपनी मुख्य रूप से कच्चा माल गुजरात से खरीदती है। कंपनी की विनिर्माण इकाई रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है और एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है, इससे कंपनी को परिचालन लाभ मिलता है क्योंकि परिवहन प्रक्रिया समय पर कुशल हो जाती है। वे कृषि, रसायन, निर्माण, खाद्य, दवा और खनन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। बल्ककॉर्प इंटरनेशनल का ग्राहक आधार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूरोप, मिस्र आदि देशों में उपस्थिति के साथ दुनिया भर में फैला हुआ है। बल्ककॉर्प को मंत्रालय द्वारा वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता दी गई है।

फिजिक्स वाला ने पीडब्ल्यू एनएसएटी 2024 के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए 250 करोड़ की स्कॉलरशिप की घोषणा की

मुंबई, एजेंसी। फिजिक्स वाला, भारत की अग्रणी शिक्षा कंपनी, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप सामान्य प्रवेश परीक्षा 2024 के तीसरे संस्करण के शुभारंभ के साथ शिक्षा की पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बदलने जा रही है। पीडब्ल्यू एनएसएटी सबसे बड़ा स्कॉलरशिप परीक्षा है। इस पहल का उद्देश्य नीट-यूजी और आइआइटी-जेइइ परीक्षाओं में स्कॉलरशिप हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करना है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ह्स्न्न 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन अब खुल गया है, जिसमें देशभर के छात्रों को इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का मौका दिया गया है।

परीक्षा 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन और 6 और 13 अक्टूबर को ऑफलाइन - 2024 में चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, जो सभी छात्रों के लिए सुलभ हैं। यह कार्यक्रम कक्षा वीआइ से एक्सआइआइ तक के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें पीसीएम/पीसीबी समूह शामिल हैं, जिससे यह व्यापक रूप से समावेशी है। महत्वपूर्ण रूप से, परीक्षा रजिस्ट्रेशन निशुल्क है। परिणाम नवंबर 2024 में घोषित किए जाएंगे।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की वित्त वर्ष 25 की प्रथम तिमाही में स्टैंडअलोन कुल आय में 59 प्रतिशत की वृद्धि

मुंबई, एजेंसी। पूंजी बाजार में कस्टमाइज सॉल्यूशंस का विस्तृत रेंज ऑफर करने वाली एक टेक्नोलॉजी चालित वित्तीय सेवा प्रदाता, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 30 जून 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है. प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड के सीईओ एवं पूर्णकालिक डायरेक्टर, श्री सचिन गुप्ता ने कहा, हम वित्त वर्ष 25 की प्रथम तिमाही के हमारे अपवादात्मक प्रदर्शन की घोषणा करते हुए रोमांचित है. इसमें हमारी कंसोलिडेटेड कुल आय 51 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 421 करोड़ रुपए पर पहुंच गई. हमारे स्टैंडअलोन ऑपरेशन ने और अधिक प्रभावशाली परिणाम दर्शाया है. कुल आय मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि समेत 59 प्रतिशत वृद्धि के साथ 331 करोड रुपए पर पहुंच गई. यह परिणाम हमारी व्यूहनीति की प्रभावकारिता और इनोवेशन के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

एसबीआई म्यूचुअल फंडद्वारा निवेशकों के लिए एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड योजना

मुंबई, एजेंसी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप निवेशकों के लिए एक नया फंड एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का आरंभ किया है। यह फंड मुख्यतः ओपन-एंडेड श्रेणी में है। नई रणनीतियों और अवधारणाओं को भुनाने की चाहत रखने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित विकल्पोमें निवेश करके निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना, यह इस फंड का मुख्य निवेश उद्देश्य है। हालाँकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि, योजना के निवेश उद्देश्य पूरे होंगे। इस फंड के लिए निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क इंडेक्स होगा।

नए फंड के लॉन्च पर बोलते हुए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. शमशेर सिंह ने कहा, आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विकसित भारत का केंद्र बिंदु इनोवेशन बन गया है। स्टार्ट अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया स्टैक जैसी पहलों के माध्यम से स्कूल से लेकर उद्योग तक नवाचार की संस्कृति और मजबूत बनाना यह सरकार का लक्ष्य है। एक बड़े उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ एक संपन्न स्टार्टअप और निवेश अर्थव्यवस्था वर्तमान में हमारे देश को नवाचार क्षितिज पर एक नेता के रूप में उभरने के लिए कई अनुकूल कारक प्रदान कर रही है। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए लगातार नवाचार कर रहे और ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले तत्वों में मूल्य जोड़ने के लिए अलग तरीके से काम कर रहे कंपनियों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक शानदार अवसर है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक और सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. डी. पी. सिंह ने कहा, हमने ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा, मीडिया और मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ई-कॉमर्स और उद्योग जैसे क्षेत्रों में नवाचार द्वारा संचालित कई बदलावों और उथल-पुथल का अनुभव किया है। सरकार और निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग से नवाचार पर आधारित नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि, हमारा देश प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

गोदरेज लॉक्स के सुरक्षित रहें, स्वतंत्र रहें' कैंपेन में बताया गया जेड घर की सुरक्षा के लिए अपना रहे स्मार्ट प्रौद्योगिकी

मुंबई, एजेंसी। डिजिटल नेटिव के रूप में, जेन जेड तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में बड़ा हुआ है, जिसने सुविधा, गति और नवाचार के लिए उनकी अपेक्षाओं को आकार दिया है। स्मार्ट होम तकनीक उनकी जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन गई है, जिसमें उनके रहने की जगह को दूर से नियंत्रित और मॉनिटर करने की क्षमता है। गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के हिस्से गोदरेज एंड बॉयस के लॉक्स एंड आर्किटेक्चरल फिटिंग्स एंड सिस्टम्स बिजनेस यूनिट द्वारा %लिव सेफ, लिव फ्रीली' अध्ययन से पता चलता है कि जेन जेड के 55 प्रतिशत उत्तरदाता स्मार्ट लॉक में गतिशीलता सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके सामाजिक जीवन और घर की सुरक्षा के प्रबंधन में सुविधा और लचीलेपन की उनकी इच्छा को उजागर करता है। इस तकनीक-प्रेमी पीढ़ी के लिए, स्मार्ट होम सुरक्षा केवल एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है।

गोदरेज लॉक्स एंड आर्किटेक्चरल फिटिंग्स एंड सिस्टम्स के बिजनेस हेड श्याम मोटवानी ने कहा, हमारे %रुद्ब1द्ग स्ड्डद्बद्ग, रुद्ब1द्ग स्नह्म्द्गद्गद्य4' सर्वेक्षण के दूसरे चरण के निष्कर्ष जेन जेड व्यक्तियों के बीच एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जो प्रौद्योगिकी पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है।

वेस बॉल ने प्लेनेट ऑफ द एप्स की ग्लोबल कहानी में एक नई जान फूंक दी

मुंबई, एजेंसी। किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के साथ वेस बॉल ने प्लेनेट ऑफ द एप्स की ग्लोबल कहानी में एक नई जान फूंक दी है। यह कहानी सीज़र के साम्राज्य की कई पीढ़ियों बाद की पृष्ठभूमि में स्थित है। यह वानरों का युग है, जो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, जबकि मनुष्यों को छिपकर रहना पड़ता है। इस युग में एक नया अत्याचारी वानर नेता अपना साम्राज्य बना रहा है, तभी एक युवा वानर इतिहास से मिली हर जानकारी पर सवाल खड़ा करके एक संघर्षपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ता है। उसके द्वारा चुने गए विकल्प वानरों और मनुष्यों, दोनों के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। 2 अगस्त को डिज़्नी+ हॉटस्टार पर प्रसारित हो रही इस भव्य फ्रैंचाइज़ी की नई कहानी इस महागाथा को आगे बढ़ाएगी और दर्शकों को प्रेरित एवं रोमांचित कर देगी। यह फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध होगी।

बचपन से ही इस फ्रैंचाइज़ी से अपने प्रेम का बारे में डायरेक्टर वेस बॉल ने कहा, मैं इस फ्रैंचाइज़ी की फिल्में बचपन से देखता आया हूँ। जब मैंने ओरिजनल' 68 प्लैनेट ऑफ़ द एप्स देखी, तब मैं बहुत छोटा था। एक बच्चा इस तरह की ओल्ड मूवी देखे, यह कुछ अजीब है। लेकिन पिछली तीन फिल्में बहुत शानदार थीं, जिनमें बहुत बड़े किरदार थे।

पुलिस ने ससुर की हत्या करने वाली बहु को किया गिरफ्तार

औबेदुल्लागंज। देहाती मर्ग हमीदीया अस्पताल भोपाल से प्राप्त होने पर थाना औबेदुल्लागंज में असल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, मर्ग जांच में पाया कि दिनांक 25.07.2024 को मृतक की बहु सुनीता व बड़े बेटे रूपसिंह की लड़ाई झगड़े में मृतक रामसिंह जाटव द्वारा बीच-बचाव करते समय आरोपिया बहु सुनीता ने जान से मारने की नियत से ससुर के पेट में छूरी मार दी जिससे रामसिंह जाटव की दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। जांच पर अपराध धारा 103(1) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे के निर्देशन में तथा एसडीओपी औबेदुल्लागंज श्रीमती शीला सुराणा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरी0 भरत प्रताप सिंह को हत्या की घटना कारित करने वाली आरोपिया की टीम बना कर तलाश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त आरोपीगणो की तलाश हेतु टीम बना कर, मुखबिर मामूर कर सघनता से तलाश शुरू की गई, तकनिकी साक्ष्य व अन्य स्त्रोतो से आरोपिया सुनीता जाटव सतलापुर जोड़ के पास अपनी गुरू बहन के घर पर रूकने की जानकारी मिलने पर हमराह स्टाफ मय महिला आरक्षक के दबिश दी गई, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो अपना नाम सुनीता जाटव बताया एवं जुर्म करना स्वीकार किया एवं मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त छूरी (चाकू) मृतक के घर से बरामद किया एवं आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय से आरोपिया का जेल वारंट जारी होने से जिला जेल रायसेन दाखिल किया।

औबेदुल्लागंज पुलिस स्टॉफ द्वारा अपनी सूझ-बूझ व लगन से हत्या की आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। निरीक्षक भरत प्रताप सिंह, सउनि राजेश भदोरिया, प्रआर. आदेश चौरे, प्रआर. मंगेश भदोरिया, प्रआर. माखन उइके, अभिषेक चौधरी महिला आर. बिंदु प्रसाद, उर्मिला धाकड़, पिकीं शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

फार्मा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं, फार्मा क्षेत्र में और सुविधाएं देने का सरकार कर रही प्रयास

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में फार्मा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश की फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी है। यह पॉलिसी 2002-23 की है। प्रदेश में फार्मा के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फार्मा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री में कार्य करने के लिए युवाओं को टेक्निकल रुप से स्ट्रांग बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश में फार्मा कलस्टर डेव्लप करने की संभावनाएँ बेहतर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी देने के साथ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्किल डेव्लप करें।

जहर से व्यापारी की मृत्यु

छिंदवाड़ा। गांधीगंज व्यापारी महेश साहू 52 पिता स्वर्गीय हरिप्रसाद साहू परिवार वालों ने कोतवाली में लिखित शिकायत दी है की राज्यपाल चौक में सौरभ चौरसिया के घर पैसा लेने गए थे तो उन्होंने चाय में जहर मिलाकर दिया है या उनके परिवार वालों ने जानकारी लगी तो वहां विवांता हॉस्पिटल लेकर गए जहां उन्हें इलाज किया गया गंभीर अवस्था में उन्हें नागपुर रेफर किया गया है अभी सूचना मिली है कि वहां महेश साहू की मृत्यु हो गई है।

प्रकरण जांच में लिया: टीआई

टी.आई उमेश गोल्हानी के बताया कि पीड़ित परिवार ने शिकायत की है, जबकि आरोपी परिवार का कहना है कि उन्होने जहरन नहीं दिया है जो सकता है उसने ही खा लिया है। पुलिस ने प्रकरण जांच में लिया।

एक सहायक शिक्षक निलंबित

छिन्दवाड़ा। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक श्री पुरूषोत्तम उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि जिले के विकासखंड हर्रई की प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम उईके बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा अवकाश लिए बिना ही संस्था से अनुपस्थित रहकर आज जनसुनवाई में अपने स्वास्थ्य संबंधी कारण से स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुए। सहायक शिक्षक पुरूषोत्तम उईके का बिना सूचना/अनुमति के जनसुनवाई में उपस्थित होने का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शिक्षकीय कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक श्री उईके को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री उईके को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

कलेक्टर ने दिव्यांग को प्रदाय की ट्राइसिकल और बैसाखी

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह जिले के दूरस्थ अंचलों से आए ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्यायों की सुनवाई पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हैं। इसी कड़ी में आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत पार्थ जैसवाल ने श्रीमती मालती साहू को ट्राइसिकल एवं बैसाखी प्रदान की। ट्राइसिकल एवं बैसाखी मिल जाने से दिव्यांग श्रीमती साहू को बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण छिन्दवाड़ा पी.राजोदिया ने बताया कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत कलेक्टर ऑफिस के सामने वाले मैदान में एलिम्को जबलपुर द्वारा दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिये चिन्हाकन शिविर का आयोजन फरवरी 2024 में किया गया था। इस शिविर में श्रीमती मालती पति मनोहर साहू निवासी बोदरी पुल परासिया रोड काशी नगर छिन्दवाड़ा को चिन्हित किया गया था।

अमरवाड़ा की चिरौंजी विदेश जायेगी

चिरौंजी एवं अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट करने के संबंध में प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुवात अमरवाड़ा की चिरौंजी के एक्सपोर्ट से करने के लिये चिरौंजी व्यापारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। चिरौंजी सहित जिले के अन्य उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कार्यालय से सुश्री स्नेहल ढोके डायरेक्टर असिस्टेंट जनरल फॉरेन ट्रेड नागपुर और उनकी टीम की उपस्थिति में जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत पार्थ जैसवाल, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दिनेश वरकड़े, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ.आर.सी. शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.एच.जी.एस. पक्षवार, जिला प्रबंधक नाबार्ड श्रीमती श्वेता सिंह, एलडीएम अजय कुमार सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी, लघु उद्योग भारती संघ के प्रतिनिधि, समिति के अन्य सदस्यगण, जिले के उद्योगपति, युवा उद्यमी, अमरवाड़ा से चिरौंजी व्यापारी और फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में डायरेक्टर असिस्टेंट जनरल फॉरेन ट्रेड नागपुर सुश्री ढोके और उनकी टीम द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सपोर्ट के लिए पंजीयन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, वेबसाइट, एप और महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हुए परिवर्तनों और इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की जानकारी विस्तार से साझा की गई। उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए इच्छुक सभी उद्यमियों, व्यापारियों और एफपीओ से सबसे पहले आई.ई.सी. (इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट) पंजीयन कराने की सलाह दी, जिसके बाद उत्पाद के अनुसार आर.सी.एम.सी. सर्टिफिकेशन कराना होगा। आई.ई.सी. लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए शासकीय शुल्क 500 रुपए मात्र है तथा इसके लिए वैलिड पैन, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर टोकन और कैंसल्ड चेक की आवश्यकता होती है। एक्सपोर्ट के संबंध में इच्छुक उद्यमियों और एफपीओ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में एक एक्सपोर्ट सेल की स्थापना भी की जायेगी। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के संबंध में किसी भी तरह की क्वेरी के लिए डी.जी.एफ.टी. के पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कार्यालय नागपुर पहुंचकर भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 35 किलो तक के उत्पाद डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने एग्री एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल एसिस्टेंस स्कीम्स में एपेडा (एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) की भूमिका की जानकारी भी साझा की। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की टीम और कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए आश्वस्त किया है।

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा याला नवेगांव के अपराध क्रमांक 22/2023 व प्रकरण कमांक 09/2023 के आरोपी सिकनलाल पिता कम?मू धुर्वे उम्र 22 वर्ष को धारा 5(1)/6 एवं धारा 4(2) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तथा 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 आदवि0 में 7 वर्ष कर सश्रम कारावस एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया ने प्रकरण में पैरवी की। घटना का संक्षिप्त विवरण घटना दिनांक 21/01/2023 को पौड़िता बस स्टेटस वरुह, याला वन्ड जिला-अमरावती (महाराष्ट्र) में घूमते हुये पायी गयी, जिसे माना वस्त पुलिस एवं बाल कल्याण समिति अमरावती के समक्ष पेश किये जाने एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने पर पीडिता 07 माह की गर्भवती होना पायी गयी, जिसकी सूचना पौड़िता के परिजन को दिये जाने पर पीड़िता की माँ ने थाना वरुड़ जिला अमरावती ग्रामीण में अभियुक्त सिफतलाल के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग की घटना कारित किये जाने तथा उसके गर्भवती होने के संबंध में रिपोर्ट लेख करायी थी, जिस पर थाना परुह में अपराध क्रमांक 106/23 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख लेखबध्द की गयी थी। उक्त प्रकरण की कैस डायरी थाना नवेगांव में पदस्थ निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय को कार्यालय पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा के माध्यम से प्राप्त होते पर जांच उपरांत अभियुक्त सिनकलाल के विरुष्ट अपराध कमांक 22/23 अंलवेल धारा 376 (2) (एन), 376(3) भा.द.स. एवं धारा 4.6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबध्द कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य एवं लकों से सहमत होकर मानतीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीड़िता को 2 लाख रूपये प्रतिकार देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया।पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री द्वारा थाना नवेगांव टीम को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

मेरे छिन्दवाड़ा को किस की लगी नजर

जुन्नारदेव को जिला बनाने का विरोध

छिन्दवाड़ा। जिला बडा शांत रमणीय स्थल रहा है रमणीय शांत स्थल है ,हम पूरे जिले वासी बड़े ही हिल मिल कर जीवन को जी रहे थे , अनायास ऐसा क्या हो जाता है ,हमारे छिन्दवाड़ा को अंग भंग के तरह टुकड़े टुकड़े करने के कुचक्र चला जाता है ,हमने तो हमारे जिले के लोगों ने कभी ये मांग नहीं करी की हम को अलग करो हमारे टूकडे करो ,हम परिवार रूपी जिले भाईचारा के रूप में रह रहे थे ,हम को आप लोग अलग अलग खंड खंड में बांटो हमने तो कभी नहीं कहा ना ही सपने में भी सोचेफिर हम को क्यू बांटा जा रहा है ,हम को एक भाई से दूसरे भाई से अलग क्यों किया जा रहा है ,क्यों अलग अलग कर शासन पर कर्जे का बोझ लादा जा रहा है ,अलग करने पर जो व्यय खर्चा बढ़ेगा ,उसका बोझ हम आम जनमानस को उठाना पड़ेगा ,कोई नेता अधिकारी अपने घरों से ला ला कर पूरा नहीं करेगाहमने तो संभाग मांगा था छिन्दवाड़ा जिले को संभाग बनाया जाये ,वो तो हुआ नहीं ,उल्टा मांगने की सजा हम को खंड खंड कर अलग अलग करने की घिनौनी साजिश रची जाने लगी ,जो शर्मनाक एंव हृदय को ठेस पहुंचाने वाली है प्रदेश के प्रधान जी से निवेदन है छिन्दवाड़ा जिले को भले ही सभांग भले मत बनाओ ,परंतु अब हमारे टुकड़े के रूप में बंटवारा ना करो ,हम ये अलग होने का दंश दर्द नहीं झेल पायेंगे,हमारी गुहार हमारे निवेदन पर गौर फरमाइए,अलग होने का दंश हम आज तक नहीं भूल पाये ,उसकी आलोचना भत्सर्ना आज तक करते हैं ,भारत पाक को लेकर ,उसी कार्य को हमारे लिए आप जैसे लोग कर रहे हैं ,वहा बड़ा ही शर्मनाक है, मित्रमंडल छिन्दवाड़ा इस बंटवारे की शर्मनाक पहल की भत्सर्ना करता है अपना पूरजोर विरोध करता है

पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान शीघ्र लागू करने की मांग भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन

छिन्दवाड़ा। भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश पर को संपूर्ण मध्यप्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं श्रम मंत्री को जिलाध्यक्ष के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024 के पृष्ठ क्रमांक 135,136 एवं 136 (1) से 136 (4) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी) 1/2014/ए-16 एवं श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.1/11/अन्वे/ पाँच/ 2024/8621-870 इंदौर दिनांक 13.03.2024 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित हुई जो 01.04.2024 से प्रभावशील थी। न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के आधार किया जाता है। यह पुनरीक्षण वर्ष 2019 से लंबित था परंतु तात्कालिक प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। असाधारण पत्र पर आपत्ति की गई है जिससे इसके लागू होने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। चूंकि प्रदेश सरकार का दायित्व है कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित किए जाऐं। मध्यप्रदेश के श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान शीघ्र लागू किया जावे। जिलाध्यक्ष को संबोधित एक पृथक ज्ञापन के माध्यम से निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु ध्यानाकर्षित किया जाये। खेद का विषय है कि कतिपय विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दैनिक वेतन भोगी/अंशकालीन /आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है विभागाध्यक्षों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन दो से तीन माह की अवधि के पश्चात् किया जा रहा है जो कि वेतन भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं अंशकालीन कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों के समान 8 घंटे की या उससे अधिक की डयूटी करवायी जाती है परंतु वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है जो कि कर्मचारियों के मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंशकालीन मजदूर कर्मचारियों को श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के आदेश अनुसार वेतन भुगतान प्रत्येक माह की 01 तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाये। समस्त विभाग के अस्थायी (विनियमित) कर्मचारियों को नियमित करते हुये सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये। एवं ई.पी.एफ की कटौती की जाये।

जर्जर हो चुके शिक्षक सदन को डिस्मेंटल करने की मांग

शहीद स्मारक बनाये जाने की कांग्रेस सेवादल ने रखी मांग

छिन्दवाड़ा। नगर के व्यस्तम क्षेत्र में वर्षों से जर्जर भवन हादसे को न्योता दे रहा है, किसी भी वक्त इससे बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कांग्रेस सेवादल ने क्षतिग्रस्त हो चुके भवन को डिस्मेंटल करने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवादल ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी या फिर व्यक्तगत कारणों के चलते प्रशासन ने अभी तक इस भवन को डिस्मेंटल नहीं किया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है।

कांग्रेस सेवादल के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ओलाम्पिक ग्राउंड के सामने स्थित शिक्षक सदन का भवन अत्यंत पुराना व जर्जर हो चुका है, जारी बारिश के मौसम में भवन किसी भी वक्त धाराशाही हो सकता है जिससे जन-धन की बड़ी हानि हो सकती है, इसीलिये अविलम्ब इस भवन को नष्ट कर यहां शहीद स्मारक का पुनः निर्माण कर यहां देश के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमायें लगाई जावे।प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया है कि क्षतिग्रस्त भवन का डिस्मेंटल कर यहां शहीद स्मारक का निर्माण होने से जिले व देश के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगवाई जायेगी तो यह उनके सम्मान और बलिदान के प्रति कृतज्ञता होगी। कांग्रेस सेवादल ने कलेक्टर से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि शिक्षक सदन भवन को डिस्मेंटल कर वहां शहीद स्मारक का निर्माण अविलम्ब किया जावे। ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले, राकेश मरकाम सहित कांग्रेस सेवादल के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

कलेक्टर की मनाही के बावजूद तहसीलों में काम कर रहे प्राईवेट ऑपरेटर

आरओ बैठक में अधिकारियों को दिए थे निर्देश

चौरई। आम जन को सबसे ज्यादा किसी विभाग में काम होता है तो वह राजस्व विभाग है जिसमें तहसील में आमजन की आवाजाही बनी रहती है वहीं प्राईवेट ऑपरेटरों द्वारा कई सालों से तहसील में अपना कब्जा जमाके दलाली का कर रहे है जिसकी शिकायत भी कलेक्टर से मुख्यमंत्री को हुई है जिसके कारण छोटे छोटे काम आम जनता को बिना रिश्वत दिये नहीं होता है. इसी शिकायत को देखते हुए विगत दिनों कलेक्टोर शीलेन्द्र सिंह द्वारा छिंदवाडा जिले की तहसीलों का निरीक्षण किया गया जिसके बाद राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर द्वारा चौरई तहसील में प्राईवेट ऑपरेटरों के काम न करने को लेकर व राजस्व अभियान 2.0 में नामांतरण बंटवारें में प्रगति न होने के कारण तहसीलदार राजेन्द्र सिंह तेकाम को जमकर फटकार लगाई था वहीं प्राईवेट ऑपरेटरों को तहसील में किसी भी प्रकार का कार्य कराने को लेकर मना कर दिया गया वहीं इसके चलते तहसीलदार का स्थानांतरण चौरई से जुन्नादेव कर दिया गया वहीं इनकी जगह जुन्नारदेव से प्रीति पटेल को चौरई भेजा गया है और अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि यदि बाबूओं को काम नहीं बनता है तो उन्हें ट्रेनिंग देकर सिखाया जायें। कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना तहसील के निरीक्षण के उपरांत कलेक्टर द्वारा प्राईवेट ऑपरेटरों को तहसील में कार्य करने से मनाही का आदेश कलेक्टर द्वारा दिये जाने के बाद भी चौरई तहसील में प्राईवेट रीडर बना शशांक श्रीवास्तव जो सिवनी से डेली अपडाउन करता है अभी भी तहसीलदार का ऑपरेटर बनकर दलाली कर रहा है. वहीं नायब तहसीलदार कपूर्दा सर्किल में धर्मेन्द्र जावरे भी प्राईवेट ऑपरेटर का काम कर रहा है जिनको अभी तक तहसीलदारो ने हटाया नहीं है.

इनका कहना

'' मैंने कल ही ज्वाइन किया है मुझे इस बारे में जानकारी है, जल्द प्राईवेट ऑपरेटरों को हटा दिया जायेगा''

प्रीति पटेल ,तहसीलदार, चौरई

नानाभाऊ मोहोड के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिला

सौसर। मंगलवार को पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भेट करते हुये सौसर शहर विकास से जूडी दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा डागा द्वारा सौसर बस स्टैण्ड, आबकारी विभाग और शासकीय स्कूल में नवीन बस स्टैण्ड पर पुनर्घनत्वविकरण योजना के तहत 8 हजार स्वेअर फिट में कुल 23 करोड 87 लाख के स्वीकृति की मांग रखी। जिसमें बस स्टैण्ड पर शोपिंग कॉम्पलेक्स, बस स्टैण्ड बिल्डींग, पार्किंग, सडक की श्रृखंला का समावेश होगा। वही सिविल लाईन्स में सरकारी जमीन जिसमें सरकारी क्वार्टर्स पशु चिकित्सालय और गौशाला पर पुनर्घनत्वविकरण योजना 9 हजार पाच सौ स्वेअर फिट लागत 28 करोड 24 लाख का समावेश है। जिसमें पार्क, फायर स्टेशन, चोक शेड, सडक एवं 50 क्वार्टर्स का समावेश है। केबीनेट मंत्री विजयवर्गीय द्वारा परियोजना को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले, जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहोड, भाजपा नेता इंदरचंद्र डागा, आर्किटेक नितीन बागानी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौसम पालेवार का समावेश है।

ग्राम नेहरिया परासिया में ग्रामसभा...

डब्लू.सी.एल. के ठेकादार मजदूरों को नहीं दे रहे नियमानुसार मजदूरी

खान प्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया आदेश

छिंदवाड़ा। ग्राम नेहरिया परासिया में ग्रामसभा (मुकदम सरकार) का ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें डब्ल्यू.सी.एल.उपक्षेत्रीय प्रबंधक एवं खान प्रबंधक को अनुबंध पत्र के साथ उपस्थित होने को कहा गया था। किन्तु डब्ल्यू.सी.एल.प्राधिकरण ग्रामसभा में अनुपस्थित रहे । ग्रामसभा (मुकदम् सरकार) की सभा में डब्ल्यू.सी.एल. कामगार (ठेकादार) अपना पक्ष रखते हुये कहा कि डब्ल्यू.सी.एल. के ठेकेदार हम कामगारों के दैनिक वेतन में कटौती करते है। जबकि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर वेतन नहीं मिलते है और गांव में शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार को लेकर जो अनुबंध डब्ल्यू.सी.एल. के द्वारा किया गया था उस आधार पर शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार को लेकर आज तक किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया हैं। जिसको लेकर ग्रामसभा (मुकदम् सरकार) की अदालत में गांव की विभिन्न समस्या तथा कामगारों की बात को मुकदम सरकार के तहत सुना जिसको लेकर ग्राम सभा (मुकदम् सरकार) सार्वजनिक एवं सामुदायिक रूप से निर्णय लिया कि आगामी दिनांक 07अगस्त को पुनः डब्ल्यू.सी.एल. मामला को उपक्षेत्रीय प्रबंधक एवं खान प्रबंधक को उपस्थित होने को लेकर अपना आदेश जारी किया। इस अवसर पर मुकदम् सरकार शिवरावण, तिरगाम भोई, सुखपाल धुर्वे, मदन, मिथुन धुर्वे एवं कामगार (ठेकादार) और ग्रामीण उपस्थित रहे।

राजस्व महाभियान से खफा राजस्व अधिकारियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

सांध्य प्रकाश, विदिशा। राजस्व महाभियान से राजस्व विभाग के ही अधिकारी नाराज है। मंगलवार को जिले भर के राजस्व अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों और समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। राजस्व अधिकारी संघ द्वारा सौंपे गए राजस्व संहिता के नियमों की अनदेखी कराई जा रही है। आने वाले समय में भूमि विवाद बढ़ जाएंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का कहना था कि अभी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा का समय है। उन्हें पूरे समय अलर्ट रहना पड़ता है। कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर प्रोटोकाल भी निभाना पड़ता है। इतने कामों के साथ उन्हें राजस्व अभियान में भी काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते वे मानसिक रूप से त्रस्त हो चुके है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार को यदि अभियान में नियमों के विपरीत कार्य कराना है तो एक एसओपी जारी करना चाहिए। राजस्व अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यों से मुक्त करना चाहिए। इसके अलावा राज्य शासन स्तर से ही न्यायालय के दिवस भी तय कर देना चाहिए।

चार अगस्त को शीतलधाम में कलश स्थापना

सांध्य प्रकाश, विदिशा। दिगंबर जैन संत मुनिश्री नियम सागर सहित अन्य मुनिराजों का चातुर्मास विदिशा में होगा। इसके लिए चार अगस्त रविवार को शीतलधाम में दोपहर डेढ़ बजे कलश की स्थापना की जाएगी। मालूम हो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य नियम सागर महाराज ससंघ शीतलधाम में विराजे है। मंगलवार को उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि वस्तु स्वरुप को स्वीकार करने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक ज्ञान असत्य को स्वीकार नहीं करता इसलिये सदुपयोग की कोटी में आता है। मुनिश्री ने कहा कि ऐसा जीवन जीना चाहिये जिससे आत्मा का सदुपयोग हो, ज्ञान सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है। जैसे ही आत्मा के अंदर राग द्वेष रुपी परिणाम आते हैं तुरंत ही आत्मा का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है और यही मिथ्या ज्ञान है।

जल भराव सहित अन्य समस्याओं को दूर करने दिए निर्देश

विधायक मुकेश टंडन ने एमएलबी गर्ल्स स्कूल का किया निरीक्षण

सांध्य प्रकाश, विदिशा। मंगलवार को विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा, नगर पालिका सीएमओ अनिल विदुआ, जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर के साथ गर्ल्स एमएलबी स्कूल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया। पिछले दिनों बारिश के दौरान कई बार स्कूल परिसर और कक्षा में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी। उसको लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

विधायक ने कहा कि शिक्षा के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है ताकि विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं मिले। इस स्कूल की समस्या जल्द से जल्द दूर हो इसको लेकर प्रयास किया जा रहे हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से शैक्षणिक की गतिविधियों और स्कूल भवन से संबंधित समस्याओं को हल करने को कहा। वहीं नगर पालिका से साफ सफाई और जल निकासी को लेकर निर्देशित किया है।

इसके बाद विधायक और अन्य अधिकारी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास भी पहुंचे। जहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विधायक ने बताया कि छात्रावास में रह रहीं कुछ छात्राओं ने यहां की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी। खानपान, साफ-सफाई को लेकर यहां जांच की जा रही है। जिसके सुधार के भी निर्देश दिए गए हैं।

मंडला जिले में डायरिया से 7 लोगों की मौत, सीएमएचओ डॉ सरोते की लापरवाही

डायरिया पर लगाम नहीं लगा पा रहा है स्वास्थ्य विभाग

मण्डला/अजीत पटेल। जिले में स्वास्थ्य विभाग तथा उसके जिम्मेदारों की लापरवाही तेजी से फल-फूल रहा है। इसके पहले भी स्वास्थ्य विभाग में किये गए भ्रष्टाचार और लापरवाहियों को छुपाया नहीं जा सकता है। आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला में डायरिया जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों ने जिले में 07 मासूम आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया, जिले में स्वास्थ्य विभाग बागडोर डॉ कीर्ति चन्द्र सरोते को सौंपा गया है जबकि डॉ कीर्ति चन्द्र सरोते पर पहले से भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला जैसी लापरवाहियों का खुलासा किया जा चुका है। जहां मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार डॉ कीर्ति चन्द्र सरोते से आदिवासियों की हुई इस दर्दनाक मौत को लेकर जवाब मांगा गया तो सीएमएचओ डॉ सरोते जवाब देने तो दूर मिलने को तैयार नहीं है,अब सवाल यह उठता है कि आदीवासी बहुल्य जिला मंडला में डायरिया से हुए अब तक 07 लोगो की मौत का जिम्मेदार कौन है ? आदीवासी अंचल कहे जाने बाले जिला मंडला में जंहा के दर्जनों ग्राम के ग्रामीण पूरी गर्मी पेयजल की समस्या से तड़पते रहे, अपनी समस्याएं लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर काटते रहे किंतू पूरी गर्मी उन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई और वही बारिश शुरू होते ही जिले के आदीवासी बहुल्य गांवो में डायरिया ने अपना कब्जा जमा लिया है।

सीएमएचओ द्वारा बगैर आवेदन के दी गई पावती

जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों ने एक अलग पहचान बनाई हुई है स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों अपनी तिजोरियां भरने और दिन-रात खुलेआम भ्रष्टाचार के चलते यहां तक पहुंच चुके है कि लोगों की जान लेने तक उतर आए हैं।आदीवासी बहुल्य जिला मंडला में डायरिया से हुए आदिवासियों की इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मालामाल अभियान और तिजोरी भरो अभियान जैसे भ्रष्टचारी के चलते जहां आरबीएसके में किए गए लापरवाही एवं भ्रष्टाचार जहां स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों का गबन किया गया है तो और और जब मामले की जानकारी मांगी गई तो डॉक्टर कीर्ति चन्द्र सरोते सीएमएचओ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने तथा स्वयं के द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के गबन और भ्रष्टाचार से बचने को लेकर बगैर आवेदन के जाली सूचना का अधिकार आवेदन बनाकर पावती देकर उसे अपील में पेश कर दिया गया तथा फर्जी आवेदक बनकर फर्जी तरीके से जानकारी प्राप्त होने का अपील आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर कर मामले एवं अपील को निराकृत कर दिया गया।इस मामले को लेकर जब हकीकत जानने स्वयं आवेदक अधिवक्ता अजीत पटेल सीएमएचओ डॉ सरोते से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे तो आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर करने तथा बगैर आवेदन के पावती देकर मामला एवं अपील को रफा-दफा करने वाले करोड़ों के गबनकर्ता सीएमएचओ डॉ सरोते आवेदक से मिलने तथा जवाब देने पीछे हट गए। जिले में स्वास्थ्य विभाग की इसी लापरवाहियों और भ्रष्टाचारीयों के चलते डायरिया का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है और मंडला जिले के डायरिया से ग्रसित आदीवासीयो की जिंदगी से जुआं खेला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से रोजाना डायरिया के मरीज बड रहे हैं और डायरिया की चपेट में आए इन आदीवासी बहुल्य ग्रामों से दुर्दशा की नई-नई तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही है,इससे यही बात स्पष्ट होती है की जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों तथा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी विभाग की व्यवस्था को लेकर जरा भी संजीदगी नहीं दिखाई जिसके नतीजे आए दिन सामने आ रहे है और आदीवासी अंचल कहे जाने बाली मंडला जिला के मासूमों को जहां पहले भी आरबीएसके भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों का शिकार किया जा चुका है उन्हीं मासूम आदिवासियों को डायरिया का शिकार किया जा रहा है और अब तक इस डायरिया जैसी महाम से जिले के 07 लोगों ने अपना जान गंबा दिया और इतना सबकुछ होने के बाद भी जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं इसके जिम्मेदारों को जरा भी सरोकार नहीं है

जिले में बैठे हुए हैं सांसद और केबिनेट मंत्री- मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला में साल भर से स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचारी और लापरवाहियों का चिठ्ठा खोल-खोलकर नेता-मंत्री से लेकर आला-अधिकारियों तक स्वास्थ्य व्यवस्था की करतूतों का खुलासा किया जा चुका है और तो और इलाज के नाम पर आदिवासियों का खून चूसने वाले डॉक्टरों का उजागर भी किया जा चुका है, आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला में 08 विधानसभा के सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते, पीएचई विभाग की केबिनेट मंत्री सम्पतिया उइके जिले में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था तथा पेयजल की की इस भीषण समस्या का मुख्य कारण यही है कि विभाग में कार्यरत तथा जिम्मेदारों ने लापरवाहियों तथा भ्रष्टाचार को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया है नतीजा आये दिन मासूम आदिवासी मौत के घाट उतर रहे हैं जब जिम्मेदारों से लापरवाहियों का जवाब मांगा गया तो जिम्मेदारों ने अपना हाथ खेचते नजर आए,

पीएचई मंत्री संपतियां उईके तथा 30 वर्षों से अधिक सांसद की कुर्सी संभालने वाले फग्गनसिंह कुलस्ते से उनके गृह जिले में डायरिया फैलने से मचे हडकंप तथा स्वास्थ्य विभाग की इस भ्रष्टाचारी और लापरवाहियों से जिले में डायरिया की इस ऐंट्री और जिले में हो रही मासूमों की मौत तथा डायरिया फैलने से मचे हाहाकार जहां जिले में डायरिया के प्रकोप से 07 लोगों की मौत हो गई है जबकि पचासों ग्रामीण बीमार हो गए है।इसके पहले घुघरी के सरई टोला और आमा टोला गांव में भी डायरिया का प्रकोप फैला था जिसमें तीन महिलाओं कीं दर्दनाक मौत हुई थी और कई लोग डायरिया पीड़ित बताए जा रहे थे, डायरिया जैसी महामारी से दोनों जगह डायरिया फैलने का कारण दूषित पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही बरतने का कारण बताया जा रहा है।

सीएमएचओ लापरवाहियों का जवाब देने से छुपते नजर आ रहे- वहीं उल्टी दस्त के मरीजों की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है- और नल जल से सप्लाई होने वाले पानी से संक्रमण की आशंका को देखते सप्लाई बंद कर दी गई है- साथ ही गामीणों के लिए वैकल्पित पीने के पानी की व्यवस्था टैंकरों से की गई है- गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम के द्वारा मौके पर पहुंच कर- गांव में नल योजना से सप्लाई होने वाले पानी का सैंपल लिया गया है- और दवाई आदि का छिड़काव किया जा रहा है- किंतू सवाल यह खडा होता है की- आखिर इन ग्रामों में बारिश के पूर्व सुद्ध पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हुआ- और आज गंदे पानी के कारण- कई गांव में संक्रमण फैल गया है।

मध्य प्रदेश के 6 अफसरों को अवार्ड होगी आईएएस

भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए बड़ी खबर है। 2023 में आईएएस अवार्ड के लिए 6 पद रिक्त हुए हैं। इन सभी 6 पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस अवार्ड करने का निर्णय लिया गया है। वहीं गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस बार भी आईएएस बनने का मौका नहीं मिलेगा।

मध्य प्रदेश के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस बार भी आईएएस अवार्ड नहीं होगा। राज्य प्रशासनिक सेवा संगठन के विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस बार आईएएस अवार्ड के लिए स्वीकृत 6 पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को देने का निर्णय लिया है। सूत्रों का कहना है कि एक दो दिन में जीएडी कार्मिक आईएएस अवार्ड का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

इन अफसरों को मिलेगा मौका

जानकारी के अनुसार 2006 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों को आईएएस अवार्ड हो सकता है। इनमें नंदा भलावे कुशरे, अनिल कुमार डामोर, सविता झनिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी और जितेन्द्र सिंह चौहान के नाम शामिल हैं।

18 नामों में से चुने जाएंगे 6 नाम

इन 6 पदों पर आईएएस अवार्ड करने के लिए जीएडी कार्मिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2006 और 2007 बैच के 18 अधिकारियों के नाम पैनल तैयार किया है। दरअसल पदोन्नति के लिए हर पद पर 3 अधिकारियों के नाम शामिल किए जाते हैं। इस हिसाब से जोन ऑफ कन्सीडरेशन में 18 अधिकारियों के नाम आ रहे हैं।

पीएचक्यू ने इसलिए रोकी इंटिग्रिटी

राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी निमिशा पांडे ने अपनी वरिष्ठता तय करने को लेकर पुलिस मुख्यालय में अभ्यावेदन दिया है। उनका कहना है उनकी वरिष्ठता तय करने के बाद ही आईपीएस की डीपीसी की जाए। सूत्र बताते हैं कि इसके चलते मुख्यालय ने दो अफसरों की एंटीग्रिटी होम डिपार्टमेंट को नहीं भेजी है। हालांकि निमिशा पांडे ने 2014 में वरिष्ठता तय करने का आवेदन दिया था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब निमिशा डीपीसी के दावेदारों की सूची के कंसीडर जोन में आ रही हैं। हालांकि जूनियर होने के कारण उनका नाम इस प्रमोशन में क्लियर नहीं हो पाएगा।

ये पुलिस अफसर प्रमोशन से वंचित- सीताराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़, प्रकाश सिंह परिहार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर, दिलीप सोनी- एएसपी, उज्जैन, अवधेश प्रताप सिंह बागरी- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा, राजेंद्र वर्मा- राज्य सेवा पुलिस अधिकारी।

इन सभी अधिकारियों की जनवरी में डीपीसी होना थी। इसके बाद उन्हें आईपीएस अवॉर्ड होना था, लेकिन अभी तक डीपीसी नहीं हुई है। दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि डीपीसी नहीं होने के पीछे एक कारण इन अफसरों के अजा-जजा होना भी है। दरअसल इनमें तीन अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़ा वर्ग से है। इस कारण विभाग कोई रुचि नहीं ले रहा है।

इधर डीपीसी के चक्कर मे अटके एसीपी के प्रमोशन

दूसरी तरफ राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के प्रमोशन डीपीसी न हो पाने के कारण अटके हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 1995 और 1997 बैच के पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की डीपीसी होना थी। करीब सात महीने गुजर जाने के बाद भी डीपीसी नहीं हुई है। जबकि देश के अन्य राज्यों के इसी बैच के पुलिस अधिकारियों की डीपीसी कर उन्हें आईपीएस अवॉर्ड दिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पीएससी के हिसाब से मई तक प्रमोशन का कलेण्डर देना होता है, जुलाई लग गया लेकिन अभी पीएचक्यू से ही प्रस्ताव नहीं आया। अवधेश प्रताप बगड़ी और अमृत मीना की इंटिग्रिटि के फेर में फाइल रोक रखी है।

मामूली विवाद के बाद पड़ोसी ने की अधेड़ की हत्या

भोपाल। कोलार के कान्हाकुंज फेस- 2 में मंगलवार देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय संतोष ईटेरिया के रूप में हुई है। वह मजदूरी का कार्य करता था। हत्यारा उसका पड़ोसी है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दशरथ का संतोष से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर दशरथ ने घर के पास रखी ईंट से उसके सिर पर हमला किया, जिससे संतोष लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायमी के बाद छानबीन शुरू कर दी है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी के विद्यार्थी, जूडा, एसआर, जेआर व इंटर्न का स्टायपेंड बढ़ा

भोपाल। राज्य शासन ने मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डाक्टरों (पीजी के विद्यार्थी) के साथ सुपर स्पेशियलिटी के विद्यार्थी, इंटर्न और सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट के स्टायपेंड में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर लंबे समय से स्टायपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर वह कई बार हड़ताल भी कर चुके थे। इस बढ़ोतरी से इंटन को छोड़कर जूनियर डॉक्टर समेत अन्य को 2200 से लेकर 3300 रुपये से ज्यादा का मासिक लाभ होगा।

- **बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी**

मैनिट में दोपहिया वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित करने के विरोध में छात्र-छात्राओं का धरना मैनिट तिराहे पर चल रहा है।

जबलपुर: लेट आए बच्चों को स्कूल से निकाला, गेट पर जड़ा ताला, 300 बच्चे एक घंटे तक ग्राउंड में खड़े रहे

जबलपुर। जबलपुर में अवैध फीस वसूली और कॉपी-किताबों की मनमानी बिक्री के आरोपों से घिरे प्राइवेट स्कूल में बुधवार को हंगामा हो गया। प्रबंधन ने दो से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बच्चों को अनुशासन की बात कहते हुए बाहर निकाल दिया। मेन गेट पर ताला जड़ दिया। करीब 300 से ज्यादा बच्चे एक घंटे तक बैग लेकर ग्राउंड में खड़े रहे। मौके पर पहुंचे पेरेंट्स ने इसे गलत बताया, तो स्कूल मैनेजमेंट ने टीसी ले जाने तक की धमदी दे डाली। हंगामे के बाद करीब 8.30 बजे बच्चों को क्लास में जाने दिया गया। मामला पोलीपाथर स्थित

सेंट अलोयसिस स्कूल का है। परिजन का कहा है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन बौखलाया हुआ है। परिजन इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सेंट अलोयसिस स्कूल की प्रिंसिपल सोमा जॉर्ज के खिलाफ अवैध फीस वसूली, यूनिफॉर्म और बुक्स की बिक्री के मामले में ग्वारीघाट थाने में केस दर्ज है। उन्हें जेल भी भेजा गया था। करीब दो महीने बाद कुछ दिन पहले वह जमानत पर बाहर आई हैं।

एक दिन पहले मैनेजमेंट ने भेजा मैसेज, 7.20 बजे बंद होगा गेट

स्कूल पहुंचे एक बच्चे के पेरेंट्स देवाशीष ने बताया, 'मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने 10.57 मिनट पर मैसेज भेजा कि 31 जुलाई से सुबह 7:20 बजे मेन गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद आने वाले बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे, तो मेन गेट बंद ना करते हुए कैंपस का वो गेट बंद कर दिया, जहां से बच्चे क्लास रूम में जाते हैं। इसके बाद बच्चे ग्राउंड में खड़े हो गए। ऐसे करीब 300 बच्चे थे, जो दो से 5 मिनट लेट हुए।

इधर, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि इस तरह किसी भी स्कूल की हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह मनमानी करेंगे, तो स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा।

बेसमेंट क्लास

भोपाल की 7, इंदौर की 17 लाइब्रेरी-कोचिंग सील ग्वालियर में 3 संस्थानों पर ताला लगा

इंदौर/भोपाल। दिल्ली की राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरने से तीन स्टूडेंट्स की मौत के बाद मध्यप्रदेश में भी कोचिंग संस्थानों पर सख्ती शुरू हो गई है। भोपाल में बेसमेंट में चल रहीं 7 कोचिंग और दफ्तरों को सील कर दिया गया। वहीं, इंदौर में 17 संस्थानों पर कार्रवाई की गई। इनमें 13 लाइब्रेरी बेसमेंट में और 4 कोचिंग प्लाईवुड की छत के नीचे संचालित हो रही थीं। ग्वालियर में भी तीन संस्थानों को सील किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था, यह गंभीर घटना है और एमपी में ऐसी स्थितियों से निपटने के निर्देश कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। कलेक्टर जिलों में किए गए इंतजामों की प्राथमिक रिपोर्ट जल्दी ही देने वाले हैं। वहीं, मध्यप्रदेश शासन ने सभी 16 नगर निगम कमिश्नरों से भी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों, धर्मशालाओं की रिपोर्ट मांगी है।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बनाई गई टीम ने मंगलवार को एमपी नगर जोन 2 में चल रहीं कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण किया। इनमें बेसमेंट में संचालित की जा रही 7 कोचिंग क्लासेस को सील कर दिया गया। इधर, शहर में बेसमेंट में सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही नहीं चल रहीं बल्कि कई दुकानें, ऑफिस और छोटे-मोटे वर्कशॉप भी चल रहे हैं।

जिन पर कार्रवाई की गई उनमें कौटिल्य अकादमी, द लैंप क्लासेस, अनएकेडमी सेंटर, रेजोनेंस क्लासेस, स्टेप अप अकादमी, नीट मेंटर, फिजिक्स वाला कोचिंग व अन्य क्लासेस शामिल हैं। इनमें बिना अनुमति के बेसमेंट में संचालित होते पाई गई कोचिंग क्लासेस के अलावा पार्किंग की जगह अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग होना पाया गया। इसके अलावा यहां पर सुरक्षा के इंतजामों की भी अनदेखी की जा रही थी। इन कोचिंग क्लासेस को सील करके इन्हें नसीहत दी गई है। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने बताया, जांच में पता चला कि बिल्डिंग के बेसमेंट में पढ़ाई होती है। जब टीम मौके पर पहुंची, तब बेसमेंट में पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो इसलिए बेसमेंट और ऑफिस सील कर दिया। ऊपरी हिस्से में पढ़ाई चल रही है।

कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं

एक महीने पहले हुए फायर सेफ्टी ऑडिट में पाया गया था कि कई कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में एमपी नगर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा और भोपाल विकास प्राधिकरण के इंजीनियर एवं अन्य अधिकारी भी शामिल थे।

इंदौर में 17 इंस्टीट्यूट पर एक्शन

इंदौर में भी कुल 17 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में मां शारदा लाइब्रेरी, ज्ञान पंख लाइब्रेरी और अभ्यास लाइब्रेरी समेत 13 लाइब्रेरी को सील किया गया। इनका संचालन बेसमेंट में हो रहा था। इनमें आने-जाने का एक ही रास्ता था। स्कॉलर्स करियर अकादमी का क्लासरूम भी बेसमेंट में मिला। एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में जांच के दौरान विवेकानंद इंस्टीट्यूट कोचिंग, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी हाउस, ड्रीम अचीवर्स लाइब्रेरी और ज्ञानोदय लाइब्रेरी लोहे के एंगल और प्लाई की छत के ऊपर बिना अनुमति चलती मिलीं। टीम ने इन्हें भी सील कर दिया। एसडीएम धनगर ने कहा कि इन कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्वालियर में 3 कोचिंग संस्थानों पर लगा ताला

लक्ष्मीबाई कॉलोनी में टीम बेसमेंट में चल रहीं कोचिंगों में पहुंची। यहां पार्किंग में कोचिंग क्लास का सेटअप और स्टूडेंट्स मिले। निगम की टीम ने तीन कोचिंग क्लास के तलघरों पर ताला लगाकर सील कर दिया है। उनसे कागजात मंगाए हैं। इन तीन कोचिंगों को सील किया- कॉमर्स वर्ल्ड क्लासेस, बीएस राजपूत कोचिंग और एमजीडी भौतिकी कोचिंग।

सस्ते सिलेंडर के लिए लाड़ली के नाम कनेक्शन होना जरूरी, रिकॉर्ड में कुल 98 लाख महिलाएं पात्र

भोपाल। मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना में शामिल जिन महिलाओं के नाम पर पहले से रसोई गैस कनेक्शन हैं। उन्हें ही 388 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गैस सिलेंडर के लिए 450 देने होंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति के नाम पर रसोई गैस के कनेक्शन हैं, और अब अगर पति लाड़ली बहना योजना में शामिल अपनी पत्नी के नाम पर गैस कनेक्शन लेंगे तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह स्पष्ट किया है और कहा है कि अधिकारी सब्सिडी की रिपोर्ट देते समय इसका ध्यान रखेंगे।

मंत्री ने बताया- जब लाड़ली बहनों के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी, तब जिन लाड़ली बहनों के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन था। उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर अमल के बाद गैस कनेक्शन बदलकर महिलाओं के नाम पर कनेक्शन लेने की कोशिश की है, उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार के रिकॉर्ड में कुल 98 लाख महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। जिसमें लाड़ली बहना और उज्जवला योजना से गैस सिलेंडर का कनेक्शन पाने वाली महिलाएं शामिल हैं।

40 लाख लाड़ली बहना, बाकी उज्जवला योजना कनेक्शन धारक

मंत्री राजपूत से पूछा गया कि लाड़ली बहना योजना में कुल कितनी पात्र महिलाएं हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसके स्पष्ट आंकड़े फिलहाल हमारे पास नहीं हैं। लेकिन, कुल आंकड़ा 98 लाख महिलाओं का है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को रसोई गैस सब्सिडी के लिए पात्र लाड़ली बहनों की संख्या 40 लाख बताई है तो बाकी महिलाएं उज्जवला योजना की होंगी और कुल संख्या 98 लाख है।

विपक्ष के नेता और कमलनाथ गलत आरोप लगाते थे

मंत्री राजपूत ने यह भी कहा कि विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह आरोप लगाते थे कि लाड़ली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जबकि प्रदेश सरकार घोषणा के बाद से 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि सरकार ने जो कहा है वह किया है। राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 838 रुपए एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत है जिसमें से 388 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमत्री डॉ. मोहन यादव ने राखी के त्यौहार के लिए 250 रुपए सभी लाड़ली बहनों को देने के लिए घोषणा की है। एक अगस्त को बहनों के खाते में यह राशि जमा हो जाएगी।